https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'उत्तर प्रदेश का यह चुनाव जातिवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को ख़त्म करने का चुनाव है'

वर्ष-12, अंक-05, 01-15 मार्च, 2017 (पाक्षिक) ₹20

महाराष्ट्र और ओडिशा में भाजपा की भारी जीत

मुकाबले से बाहर होती कांग्रेस, भाजपा का बढ़ता जनाधार

कृषि क्षेत्र दहाई के आंकड़े में वृद्धि की ओर

पीएसएलवी-सी 37 ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में रोड शो के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते श्री अमित शाह

सुलतानपुर (उप्र) में चुनावी जनसभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

देवरिया (उप्र) में चुनावी जनसभा को संबोधित करते श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 महाराष्ट्र में खिला कमल

महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं और जिला परिषदों के लिए हुए चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की अगुआई में राज्य सरकार ने जनहित में...

वैचारिकी

राष्ट्र जीवन की समस्याएं 16

श्रद्धांजलि

अप्रतिम क्रांतिकारी वीर सावरकर 18

लेख

मुकाबले से बाहर होती कांग्रेस, भाजपा का बढ़ता जनाधार 21

कृषि क्षेत्र दहाई के आंकड़े में वृद्धि की ओर 22

साक्षात्कार

पी.मुरलीधर राव, *राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा* 19

उ.प्र. विधानसभा चुनाव प्रचार

'सपा-बसपा सरकार ने बुंदेलखंड के साथ अन्याय किया' 24
(जालौन - फूलपुर, फतेहपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी)

'अखिलेशजी आपके काम नहीं कारनामे बोलते हैं' 26
(इलाहाबाद- कौशांबी, गोरखपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी, महोबा और बांदा)

अन्य

पीएसएलवी-सी 37 ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों... 29

ई-वीजा सुविधा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं विदेशी पर्यटक 30

कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के अधिग्रहण... 31

कृषि की विकास दर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमानः राधा मोहन सिंह 32

संगठनात्मक गतिविधियां

10 ओडिशा में भाजपा की भारी जीत

हाल ही में पांच चरणों में संपन्न हुए ओडिशा जिला पंचायत चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। अभी तक प्राप्त चुनाव...

सरकार की उपलब्धियां

13 कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 271.98 मिलियन टन होने का अनुमान

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2016-17 के लिए मुख्य फसलों के...

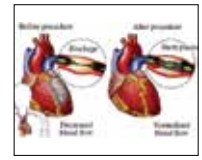

14 देश के सभी हृदय रोगियों के लिये राहतः अनंत कुमार

सबके लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री...

15 'ताम्र' पोर्टल और मोबाइल एप लांच

आम बजट को देश में बदलावों की दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@rajnathsingh

हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं।

@rsprasad

उत्तरप्रदेश में काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। यहां अपराध बोलता है।

@JPNadda

प्रदेश में विकास के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। यूपी की सरकार विपरीत दिशा में चल रही है, प्रदेश का विकास रुका हुआ है, अब भाजपा ही विकल्प है।

@byadavbjp

मुख्यमंत्री अखिलेश बताएं कि भारत सरकार के द्वारा भेजा गया शहरी विकास मिशन का पूरा पैसा उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए खर्च क्यों नहीं किया?

facebook

यूपी में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा की सुविधा न देकर यूपी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है... ये कैसा काम बोलता है?

दशकों पहले पूर्वी यूपी के विकास के लिए पटेल समिति ने एक रेल लाइन बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने इस काम की शुरुआत की है। गुजरात के कांडला पोर्ट से गोरखपुर तक गैस पाइपलाइन बिछ रही है। इससे यूपी में कारखाने खुलेंगे, रोजगार बढ़ेगा और विकास का एक नया मार्ग बनेगा।

देश के सर्वांगीण विकास के लिए जरुरी है कि हर क्षेत्र का समान विकास हो। हमारा लक्ष्य है - अन्य क्षेत्रों की तरह ही पूर्वांचल का भी विकास हो। सपा, बसपा चाहती है कि यूपी में स्थिर सरकार न बने। यूपी का विकास न रुके, इसलिए जनता से मेरी अपील है कि पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाएं।

-नरेन्द्र मोदी

भाजपा शासित राज्य जहां विकास की नित नई कहानी लिख रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश विकास में आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चला गया है।

-अमित शाह

व्यंग्य चित्र

पाथेय

हमारी सभ्यता 5000 से भी अधिक वर्ष पुरानी है। इन सब शताब्दियों में इस भूमि के जन-जन के एक समान मूल्य, विश्वास और रीति-रिवाज रहे हैं। चाहे उनका प्रदेश अथवा पंथ जाति या भाषा कोई भी हो। अपनी अनेक विविधताओं के होते भी सहस्त्रों वर्षों से हमारे इस राष्ट्र ने एक ऐसी साझा जीवन-शैली स्थापित की है, जिसकी जड़ सबकी साझी सांस्कृतिक विरासत में निहित है। यही साझा जीवन शैली भारत की अद्वितीय देन है, जिसे हम हिन्दुत्व अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। आप इसका कोई भी अन्य नाम- भारतीयता या इंडियन रख सकते हैं, किंतु मूल वही रहता है।

-कुशाभाऊ ठाकरे

पंचायत से पार्लियामेंट तक खिलता कमल

जैसे-जैसे विभिन्न चरणों में उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करती जा रही है सपा-कांग्रेस-बसपा के हाथ-पांव फूलते जा रहे हैं। प्रदेश के पिछड़ेपन से संबंधित तीखे प्रश्नों से बचने के लिए ये जाति-संप्रदाय की विभाजक राजनीति का सहारा ले रहे हैं। विकास एवं सुशासन के सवालों को दरकिनार करने के कारण प्रदेश की जनता सपा-कांग्रेस-बसपा को इस बार ऐसा सबक सिखाने जा रही है कि वे लंबे समय तक याद रखेंगे। देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस प्रदेश को विकास एवं सुशासन में अग्रणी होना चाहिए था परन्तु यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, बलात्कार एवं पिछड़ापन में सबसे आगे दिखाई देता है। सपा-बसपा के बारी-बारी के कुशासन से प्रदेश की कमर टूट चुकी है और अब जनता इनके स्वार्थी, भ्रष्ट, परिवारवादी राजनीति से पीछा छुड़ाने के लिए मतदान कर रही है। भाजपा जन-जन के लिए नई आशा बनकर उभरी है और प्रदेश के कोने-कोने में भारी जनसमर्थन प्राप्त कर रही है।

उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनावों के बीच महाराष्ट्र एवं ओडिशा की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। ओडिशा जहां अब तक भाजपा एक बड़ी ताकत नहीं मानी जाती थी, सत्तासीन बीजद के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों में बीजद को भारी झटका देते हुए भाजपा प्रदेश में एक बड़ी पार्टी बन गई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हुए चुनावों में दस में से आठ महानगरपालिका में भाजपा विजय हुई। बीएमसी में भी भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए शिवसेना से मात्र दो सीटें ही कम प्राप्त की। इतना ही नहीं जिला परिषद एवं पंचायतों में भी पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रदर्शन से सभी लोग अचंभित हैं। किसी ने भी इतने कम समय में इतनी बड़ी जमीनी परिवर्तन की उम्मीद नहीं की थी। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, चण्डीगढ़ में भी हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में भी भाजपा ने भारी विजय हासिल की है। यह एक ऐसी बयार है जो पूरे देश में दिखाई दे रही है- भाजपा जिन प्रदेशों में पहले बड़ी ताकत नहीं थी अब वहां के सत्ताधारियों को चुनौती दे रही है और जहां सत्ता में थी वहां उसका जनसमर्थन और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। यह वास्तव में देश में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है जब भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, भाई-भतीजावाद एवं परिवारवाद की राजनीति के स्थान पर विकास, सुशासन एवं परफोर्मेंस की राजनीति मजबूत हो रही है। जो लोग वोट-बैंक और तुष्टीकरण की सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास रखते हैं उन्हें जनता अब धूल चटा रही है।

भाजपा की कड़ी मेहनत का परिणाम आना अब शुरू हो गया है और अपार जनसमर्थन हर ओर भाजपा को मिल रहा है। गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, महिला एवं युवा के लिए बनी एक से बढ़कर एक नीतियों से वंचित-शोषित वर्गों का विश्वास भाजपा पर और अधिक मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनपर गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अटूट विश्वास है। इतना ही नहीं समाज का हर वर्ग उन्हें करिश्माई द्रष्टा के रूप में देखता है जो पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार, लूट-खसोट एवं सत्ता के बिचौलियों से मुक्त करने को कृतसंकल्प है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह निरंतर पार्टी को पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक में मजबूत करने पर बल देते रहे हैं। साथ ही उन प्रदेशों के लिए उन्होंने विशेष योजना भी लाया जहां पहले भाजपा की राजनैतिक उपस्थिति अधिक मजबूत नहीं मानी जाती थी। पार्टी की कड़ी मेहनत का परिणाम आना अब शुरू हो गया है और अपार जनसमर्थन हर ओर भाजपा को मिल रहा है। गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, महिला एवं युवा के लिए बनी एक से बढ़कर एक नीतियों से वंचित-शोषित वर्गों का विश्वास भाजपा पर और अधिक मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिन पर गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अटूट विश्वास है। इतना ही नहीं समाज का हर वर्ग उन्हें करिश्माई द्रष्टा के रूप में देखता है जो पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार, लूट-खसोट एवं सत्ता के बिचौलियों से मुक्त करने को कृतसंकल्प है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी लंबी निद्रा से जागकर एक विकसित, सुदृढ़ एवं वैभवपूर्ण राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार का जनसमर्थन भाजपा की सभाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है उससे कहा जा सकता है कि पूरे देश में जो हवा बह रही है उससे उत्तर प्रदेश अपवाद नहीं है। लोग विकास, सुशासन एवं परफॉर्मेंस की राजनीति के पक्ष में भारी मतदान कर रहे हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

महाराष्ट्र में खिला कमल

10 में से 8 महानगरपालिका चुनावों में भाजपा ने लहराया परचम

महाराष्ट्र में महानगरपालिकाओं और जिला परिषदों के लिए हुए चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की अगुआई में राज्य सरकार ने जनहित में अनेक कदम उठाए, जिसका लाभ भाजपा को मिला। चुनाव-प्रचार के दौरान नोटबंदी को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि देश की जनता को इस फैसले से परेशानी हुई है और चुनावों में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में अपना मत देकर नोटबंदी फैसले पर फिर एक बार मुहर लगा दी। इससे पूर्व नोटबंदी के पश्चात् हुए चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और हरियाणा के स्थानीय और पंचायत चुनावों में भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा।

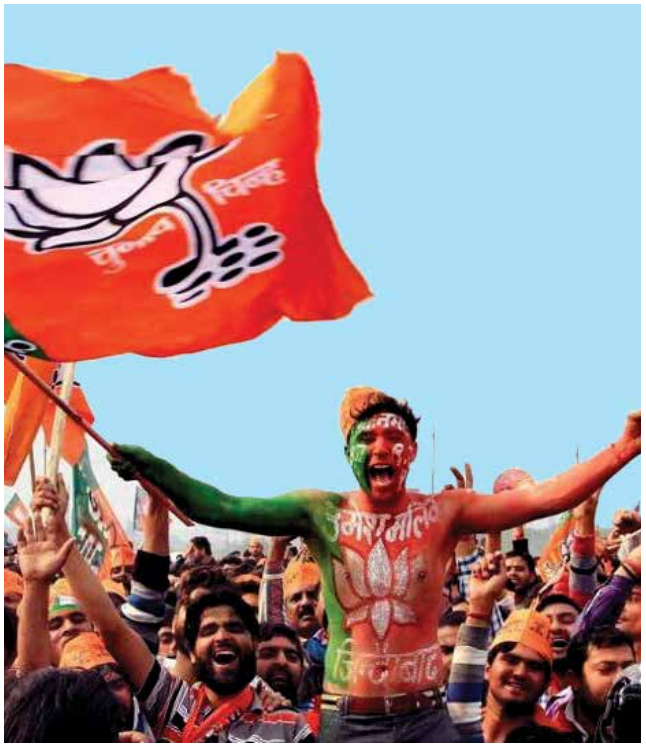

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित 10 महानगरपालिका और 25 जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की। ठाणे को छोड़कर उल्हासनगर, पुणे, नासिक, नागपुर, पिंपरी-चिंचवड़, अमरावती, अकोला और सोलापुर में भाजपा का कमल खिला। भाजपा ने ऐसे क्षेत्रों में भी जीत हासिल की जहां अतीत में वह कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी थी। कांग्रेस-राकांपा को तगड़ा झटका लगा।

महाराष्ट्र में 10 महानगरपालिकाओं के नतीजे की बात करें तो भाजपा को 624, शिवसेना को 268, कांग्रेस को 102 राकांपा को 139, मनसे को 16 और अन्य को 99 सीटों पर जीत मिली। अकेले दम पर चुनावों में उतरी भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ।

मुंबई

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा फायदे में भाजपा रही। बृहनमुंबई नगर निगम (बीएमसी) की 227 सीटों के लिए हुए चुनाव में शिवसेना को 84 सीटें मिलीं, वहीं भाजपा ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 31 सीटों से संतोष करना पड़ा। राकांपा को 9, मनसे को 7 और अन्य को 14 सीटें मिलीं।

नागपुर

भाजपा का गढ़ माने जाने वाले नागपुर में पार्टी के प्रदर्शन में जबरदस्त उछाल आया। 2012 के चुनाव में यहां भाजपा ने कुल 145 में से 62 सीटें जीती थीं, इस बार 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया।

पुणे

2012 के चुनाव में कुल 152 सीटों में से भाजपा ने 26 सीटें जीती थीं। इस बार भाजपा ने अपनी सीटों को तिगुने से भी ज्यादा कर लिया। भाजपा ने 96 सीटों पर जीत हासिल की।

उल्हासनगर

यहां भी भाजपा ने पिछले चुनाव के प्रदर्शन को काफी सुधारा। कुल 78 सीटों में से पिछली बार की 11 सीटों की तुलना में भाजपा ने 32 सीटें अपनी झोली में कर ली।

मनपा चुनाव 2017						
मनपा	भाजपा	शिवसेना	कांग्रेस	राकांपा	मनसे	अन्य
मुंबई	82	84	31	09	07	14
अकोला	48	08	13	05	00	06
ठाणे	23	67	03	34	00	04
पुणे	96	10	10	40	02	04
पिंपरी चिंचवाड़	78	09	00	35	00	06
नागपुर	108	02	29	01	00	11
नासिक	63	35	06	07	07	04
सोलापुर	49	21	14	04	00	14
अमरावती	45	07	15	00	00	20
उल्हासनगर	32	25	01	04	00	16
जिला पंचायत 2017	भाजपा	शिवसेना	कांग्रेस	राकांपा	मनसे	अन्य
	409	273	308	360	0	168

नासिक

भाजपा ने नासिक में शानदार प्रदर्शन किया। 122 सीटों में से 2012 में जहां पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिली थीं, वहीं इस बार 63 स्थानों पर विजय प्राप्त की।

ठाणे

ठाणे में शिवसेना की बढ़त कायम रही, लेकिन भाजपा के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ। भाजपा ने यहां पिछले बार यहां 8 सीटें जीती थीं, इस बार यह आंकड़ा लगभग तिगुना हो गया और पार्टी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की।

अकोला

कुल सीटें 71 में से भाजपा ने 2012 में 18 सीटें जीती थीं, पर इस बार 48 स्थानों पर शानदार जीत हासिल की।

अमरावती

कुल 87 सीटों में से भाजपा को 7 सीटें मिली थीं। इस बार भाजपा ने 45 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया।

सोलापुर

कुल 102 सीटों में से 2012 के चुनाव में भाजपा ने 26 सीटें जीती थीं। इस बार पार्टी का 49 सीटों पर कमल खिला।

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में भी भाजपा का परचम

5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे भाजपा के लिए काफी उत्साहजनक रहे। न केवल निकाय चुनावों, बल्कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों में भी भाजपा ने पिछली बार से बड़ी बढ़त हासिल की। निकाय चुनावों की तरह ही इन दोनों चुनावों में भी भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को 409, शिवसेना को 273, कांग्रेस को 308 एवं राकांपा को 360 सीटें मिलीं तथा अन्य के खाते में 168 सीटें गईं।

इसी तरह 118 पंचायत समितियों की 2809 सीटों में से 803 पर जीत दर्ज कर भाजपा यहां भी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 630 सीटों के साथ राकांपा दूसरे, 555 सीटें जीतकर कांग्रेस तीसरे और 538 सीटें लेकर शिवसेना चौथे नंबर पर रही।

पिंपरी चिंचवड़

कुल सीटें 128 में से पिछली बार भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं जबकि इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए पार्टी ने 78 स्थानों पर विजय प्राप्त की. ■

भाजपा नेता बोले...

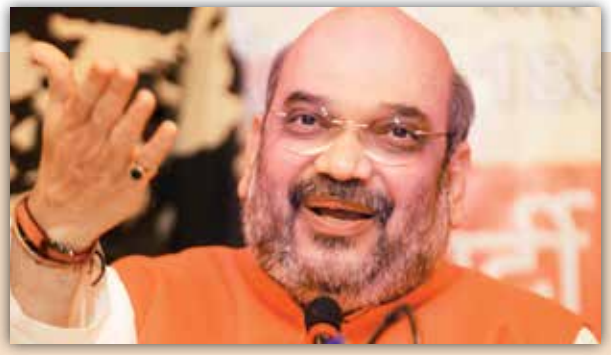

महाराष्ट्र की जनता का हृदय से अभिनंदन: अमित शाह

मुंबई महानगरपालिका समेत महाराष्ट्र के सभी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा, ''इस अभूतपूर्व सफलता के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष श्री रावसाहेब दानवे पाटिल एवं महाराष्ट्र के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और भाजपा की विकासनीति में विश्वास प्रकट करने के लिए महाराष्ट्र की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं।

निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पारदर्शिता पर जनादेश: देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा की जीत पारदर्शिता और नोटबंदी के लिए वोट किये जाने के चलते आयी है। श्री फडणवीस ने भाजपा को मिली जबर्दस्त कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'चुनावी परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देशों का नतीजा है। मैं इस जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूं।'

साल की शानदार शुरुआत: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा की विकास और सुशासन पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, "कड़ी मेहनत, समर्पण और जमीन पर काम करने की वजह से, भाजपा अब शहरी और ग्रामीण महाराष्ट्र में मजबूत शक्ति बन गई है। मैं महाराष्ट्र भाजपा की पूरी टीम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राव साहब पाटिल (राज्य भाजपा अध्यक्ष) को लोगों के बीच अथक काम करने के लिए बधाई देता हूं।" श्री मोदी ने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने कहा, "यह 2017 की शानदार शुरुआत है। पहले ओडिशा में अभूतपूर्व समर्थन और अब महाराष्ट्र के लोगों की असीम शुभकामनाएं। मैं हर एक भारतीय को भाजपा में लगातार विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम पूरी लगन से एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं।"

पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई: दानवे

महाराष्ट्र में नगर निकाय और जिला परिषद चुनावों में भाजपा की जीत को अप्रत्याशित बताते हुए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री राव साहेब दानवे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि यह जीत उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में हो रहे चुनावों में भाजपा की जीत का संकेत है।

संपादकीय टिप्पणी

बृहन्नमुंबई महानगरपालिका सहित महाराष्ट्र के दस शहरों के निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत को राष्ट्रीय समाचार–पत्रों ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में उल्लेखनीय बताया और लिखा है कि चुनाव नतीजों से भाजपा को सर्वाधिक फायदा हुआ। हम यहां समाचार–पत्रों के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं –

दैनिक जागरण

निःसंदेह निकाय चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा असर नहीं डालते, लेकिन वे राष्ट्रीय राजनीति की भावी दशा–दिशा का संकेत देने के साथ राजनीतिक दलों की जमीनी हकीकत को कहीं अधिक साफ तौर पर बयान करते हैं। मुंबई महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र के दस शहरों के निकाय चुनावों के नतीजे यदि कुछ कह रहे हैं तो यही कि नोटबंदी को चुनावी मसला बनाकर भाजपा को घेरनेवाले अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करें। यदि अपेक्षाकृत संपन्न और साथ ही देश की वित्तीय राजधानी का दर्जा रखनेवाली मुंबई में नोटबंदी को चुनावी मसला बनाकर लाभ नहीं लिया जा सका तो और कहां लिया जा सकता है? निकाय चुनाव वाले अन्य शहरों में ठाणे को छोड़ दें तो शेष के चुनाव नतीजे भी नोटबंदी को सही ठहराने के साथ भाजपा के प्रति भरोसे को जाहिर कर रहे हैं।

जनसत्ता

इस बात के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब स्थानीय निकायों के चुनावों के नतीजे लोकसभा और विधानसभा चुनाव से भिन्न रहे हों। लेकिन यह भी सही है कि महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनावों का महत्व दूसरे राज्यों के मुकाबले अधिक रहा है और इन पर काबिज होने का मतलब राज्य–स्तरीय राजनीति में भी ताकत बढ़ना है। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनावों के नतीजों से जाहिर है कि सबसे ज्यादा फायदे में भाजपा है और सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को हुआ है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को भी निराशा ही हाथ लगी है। सबसे ज्यादा नजरें बृहन्नमुंबई (बीएमसी) के चुनाव पर थीं। यहां शिवसेना पहले स्थान पर आई, और उससे कुछ ही कम सीटों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर। अलबत्ता शिवसेना 270 सदस्यीय बीएमसी में बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। 2012 में मिलकर लड़ने के बावजूद शिवसेना को सार और भाजपा को इकतीस सीटें मिली थीं। पर इस बार अलग–अलग लड़ने के बावजूद दोनों की सीटों में भारी इजाफा हुआ है। इस चुनाव का भाजपा बनाम शिवसेना हो जाना कांग्रेस और राकांपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। बाकी नगर महापालिकाओं में भी भाजपा या तो बहुमत पाने में कामयाब हो गई या फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। पुणे की नगर महापालिका भाजपा ने राकांपा के हाथ से छीन ली, तो नाशिक की मनसे से। अगर पूरे महाराष्ट्र की सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा को मिली सीटों के आधे से भी कम सीटें शिवसेना को मिली हैं, शिवसेना के आधे से भी कम पर कांग्रेस है। यह उस राज्य में कांग्रेस का हाल है जो बहुत लंबे समय से उसका गढ़ रहा।

हिन्दुस्तान

महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे भाजपा और शिवसेना के लिए भले ही जश्न मनाने का कारण लेकर आए हों, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के लिए तो बुरी खबर ही है। खास बात यह रही कि देश की सबसे बड़े बजट वाली वृहन्नमुंबई महानगरपालिका पर कब्जे का शिवसेना का इरादा उतना आसान नहीं रह गया, जितना मतगणना के शुरुआती रुझानों में लग रहा था। शिवसेना ने 2012 के मुकाबले बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन भाजपा की बढ़त का ग्राफ अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा है। निश्चित तौर पर यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के लिए राहत की खबर है, क्योंकि राज्य में निकाय चुनावों की कमान उन्हीं के हाथों में थी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भले ही कर दी हो, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी, दोनों के लिए यह सोचने का वक्त है कि अलग–अलग राह अलग–थलग ही करती है, जैसा कि उनके मामले में नतीजों ने दिखाया है। दोनों को सोचना होगा कि अब भी नजरिया और आचरण न बदला और मिलकर साथ चलने की रणनीति नहीं अपनाई, तो दोनों की राजनीति के लिए भविष्य के रास्ते बंद होने को हैं। इतना तो स्पष्ट है कि दोनों अगर साथ खड़े होते, तो इनके खाते में आज दिखाने के लिए बहुत कुछ होता।

नवभारत टाइम्स

महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव नतीजे बीजेपी को मालामाल करनेवाले रहे हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के लिए ये उतनी ही बड़ी चिंता का विषय बनकर उभरे हैं। बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस में आपसी लड़ाई जो भी हो, पर ये सब हिंदुत्व धारा की ही शाखाएं–उपशाखाएं हैं। यह धारा महाराष्ट्र में तेजी से फलती–फूलती नजर आ रही है। इसके विपरीत सेकुलर धारा की राजनीति करने वाली कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी आदि तमाम पार्टियां अचानक हाशिये पर नजर आने लगी हैं। ■

ओडिशा में भाजपा की भारी जीत

भाजपा को अभी तक 30 में से 8 जिलों में पूर्ण बहुमत

हाल ही में पांच चरणों में संपन्न हुए ओडिशा जिला पंचायत चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। अभी तक प्राप्त चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा ने 30 में से 8 जिलों में पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त की, जबकि सत्ताधारी बीजू जनता दल जिसे पिछली बार 30 में से 28 जिला परिषदों पर काबिज थी, इस बार वह घट कर 16 पर आ गई। गौरतलब है कि ओडिशा में पिछली बार 30 जिला परिषद में से एक भी जिला परिषद में भाजपा नहीं थी।

मल्कानगिरि, कालाहांडी, मयूरभंज, बरगढ़ जैसे सभी पिछड़े और आदिवासी जिलों में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत हासिल हुई है। मल्कानगिरि में जहां भाजपा को 13 में से 10 सीटें प्राप्त हुई हैं, वहीं कालाहांडी में 36 में 34, बलांगिर में 36 में 24 और मयूरभंज जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासी हैं, वहां 56 में से 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा की जनता के प्रति अपना आभार प्रकट किया और विकास यात्रा में साथ देने के लिए उनको धन्यवाद दिया। कांग्रेस का तो ओडिशा से पूर्णतया सफाया हो गया, उसे केवल एक जिला परिषद में जीत हासिल हुई। ओडिशा के इतिहास में कांग्रेस की शायद इससे बुरी दुर्गति पहले कभी हुई होगी।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा का 80% इलाका ग्रामीण क्षेत्र का है, ऐसे में राज्य के

ओडिशा की जनता को धन्यवाद: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत चुनावों में भाजपा में भरोसा दिखाने पर ओडिशा की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं ओडिशा पंचायत चुनावों में भाजपा में भरोसा और पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने ओडिशा भाजपा कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम पर उन्हें बधाई दी।

पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई: अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ओडिशा पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और ओडिशा की पंचायत चुनावों में पार्टी की अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रदेश के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।"

ओडिशा नवीन पटनायक सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहता हैः बसंत पंडा

पंचायत चुनावों में भाजपा को भारी जीत मिलने के बाद ओडिशा भाजपा अध्यक्ष **श्री बसंत पंडा** एक दूरभाष साक्षात्कार में कमल संदेश के एसोसिएट संपादक **राम प्रसाद त्रिपाठी** को कहा कि यदि बीजेडी हिंसा नहीं करती और इसकी सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती तो भाजपा की जीत और बड़ी होती। उन्होने कहा कि बीजेडी सरकार के कुशासन के दिन गिने-चुने रह गए हैं और ओडिशा बदलाव के लिए तैयार है। प्रस्तुत है मुख्य अंशः

हाल ही में संपन्न हुए ओडिशा पंचायत चुनावों में भाजपा को भारी जीत हासिल हुई है। ऐसी अभूतपूर्व सफलता के पीछे कौन से कारण हैं?

मेरे विचार से भाजपा की जीत के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, पार्टी की सांगठनिक दक्ष्यता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भाजपा दो साल पहले सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। जो सफलता के साथ ओडिशा में सम्पन्न हुआ। इससे पार्टी को बूथ एबं पंचायत स्तर पर मजबूती मिली। सदस्यता अभियान के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंचायत स्तर पर गरीबों के मुद्दों को प्रभावी व जोरदार ढंग से उठाया। साथ ही वे जन-जन के भलाई और विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस बड़ी जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को न केवल लोगों ने पसंद किया, बल्कि इसमें आस्था भी व्यक्त की है।

दूसरा कारण यह है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी केंद्र में सरकार बनाने के बाद लगातार ओडिशा के विकास के लिए विशेष ज़ोर दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने आम बजट 2017-18 में ओडिशा की रेलवे, आधारभूत संरचनाओं, कृषि की विकास के लिए और युवाओं को रोजगार मुहैया करने के लिए ऐतिहासिक राशि आवंटित की है, जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई। मोदी सरकार ने अभी तक जो भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं-जैसे ओआरओपी, सर्जिकल स्ट्राइक और विमुद्रीकरण-उसको ओडिशा की जनता ने खुलेदिल से समर्थन किया है। भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण मोदी सरकार को जनता पसंद करती है। मेरा मानना है कि यह भारी जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था को व्यक्त करता है।

भाजपा की अगली रणनीति क्या है? क्या आप मानते हैं कि आने वाले चुनावों में भाजपा के प्रति लोगों का समर्थन और बढ़ेगा?

अब भाजपा की नजर 2018 के शहरी चुनाव और 2019 के आम चुनाव पर रहेगी। हमारा ध्यान पार्टी की संगठनात्मक क्षमता को और मजबूत करने पर है। साथ ही कार्यकर्ताओं में नेतृत्व गुणों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। शहरी निकायों और 2019 के आम चुनाव में पार्टी की विजय के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लोग बदलाव के साथ ही नवीन पटनायक सरकार के कुशासन से मुक्ति भी चाहते हैं।

ऐसी खबर है कि चुनावों के दौरान बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा की। इस तरह की गतिविधियों से वे क्या संदेश देना चाहते हैं?

भारी पराजय के कारण बीजेडी के कार्यकर्ता विक्षिप्त मालूम पड़ते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता बिल्लू प्रधान की हत्या कर दी गई। इसके अलावा इन्होंने पिछले दिनों में 6 भाजपा कार्यकर्ताओं की भी हत्या कर दी हे। साथ ही तमाम भाजपा कार्यकर्ता इनकी हिंसक गतिविधियों के कारण चोटग्रस्त हैं और विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। बीजेडी सरकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराना चाहता है, लेकिन वे इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। मेरा मानना है कि यदि बीजेडी हिंसा नहीं करती और इसकी सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती तो भाजपा की जीत और बड़ी होती।

पंचायत चुनाव परिणामों से साफ स्पष्ट है कि राज्य से कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया है। ओडिशा में कांग्रेस का क्या भविष्य है? क्या आप ऐसी संभावना देखते हैं कि भाजपा को हराने के लिए बीजेडी-कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है?

पंचायत चुनावों में लोगों ने बीजेडी को नकार दिया है। वे भाजपा को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भाजपा की वैचारिक प्रतिबद्धता और विकासोन्मुखी व प्रगतिगामी नीतियों के प्रति लोगों का समर्थन है। परिणामों से स्पष्ट है कि कांग्रेस का जनाधार निरंतर घट रहा है। राज्य में अब कांग्रेस कोई प्रभावी शक्ति नहीं है। भविष्य में बीजेडी और कांग्रेस का गठबंधन होने की संभावना से मैं इंकार नहीं कर सकता। लेकिन ओडिशा के लोगों का जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेडी सरकार के कुशासन के दिन गिने-चुने रह गए हैं और ओडिशा बदलाव के लिए तैयार है। ■

भाजपा की सशक्त उपस्थिति: धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंचायत चुनावों में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के लिए ओडिशा के लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के जनहित के फैसलों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है और इसमें अपनी आस्था व्यक्त की है, उसी तरह से ओडिशा की जनता ने भी इस समर्थन को आगे बढ़ाने का काम किया है। श्री प्रधान ने कहा कि समाज के सभी तबक़ों खासकर गरीब, आदिवासी और पिछड़े तबके के लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है और उसी का परिणाम है कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी जहां अभी तक कुछ-एक इलाके तक ही सीमित रहती थी, आज वह ओडिशा के 30 जिलों में से एक को छोड़ कर हर जिले में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर अपने आप को प्रतिष्ठित करने में कामयाब हुई है।

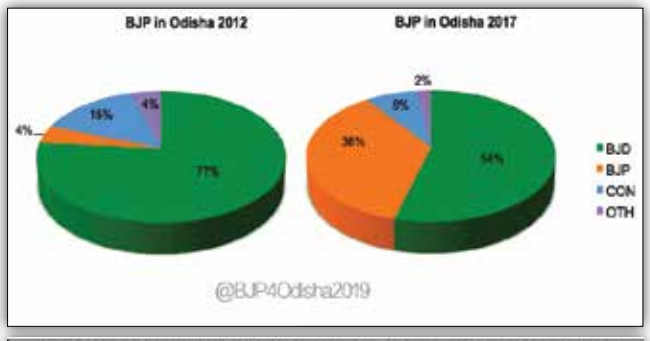

#Odisha Panchayat Poll 2017 Final Result - @Bjp4Odisha2019

Party	2012	2017	Gain/Loss
BJP	36	306	+270
BJD	651	460	-191
INC	126	66	-60
OTH	38	17	-21
Total	851	849/851	@BJP4Odisha2019

RESULT

स्थानीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही भाजपा की लोक-कल्याणकारी सरकार की नीतियों को जाता है।

श्री प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी देश भर घूम-घूम कर यह कहते-फिरते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी गरीब विरोधी हैं, उन्हें गरीबों की कोई चिंता नहीं है लेकिन तथ्य कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि 2008 में राहुल गांधी ओडिशा के कालाहांडी आये थे और उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया था कि मैं दिल्ली में आपका सिपाही बनूंगा, 2009 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत भी मिली थी, 10 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कालाहांडी से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ हो गया है। उन्होंने कहा कि कालाहांडी की कुल 36 सीटों में से 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री हासिल हुई है, इसी तरह बरगढ़ जिले में भी राहुल गांधी ने सितम्बर, 2015 में दौरा किया था और किसानों की समस्या की बात की थी लेकिन इस जिले में कांग्रेस को कोई सीट प्राप्त नहीं हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 34 में से 26 सीटों पर जीत हासिल हुई है।

श्री प्रधान ने कहा कि डिमोनेटाईजेशन के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाईजेशन के बाद देश की राजनीति में परिवर्तन आया है, हालांकि कुछ लोगों ने देश में डर और आतंक पैदा करने की कोशिश की लेकिन देश की सामान्य जनता विशेषकर देश के गरीब लोग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। मैं इसके लिए देश के जनसामान्य के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

उन्होंने कहा कि ओडिशा के जिला परिषद चुनाव में भाजपा की विजय इस बात को प्रमाणित करती हैं कि 8 नवंबर, 2016 के बाद देश के गरीबों की आस्था एवं विश्वास प्रधानमंत्री जी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की जनता ने काले-धन की लड़ाई में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का तहे-दिल से समर्थन किया है, इतना ही नहीं ओडिशा में नक्सल प्रभावित जिलों में कई नक्सल गुटों ने डिमोनेटाईजेशन के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और हिंसा में कमी आई है।

> ओडिशा के जिला परिषद चुनाव में भाजपा की विजय इस बात को प्रमाणित करती हैं कि 8 नवंबर, 2016 के बाद देश के गरीबों की आस्था एवं विश्वास प्रधानमंत्री जी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के जनसामान्य ने अभूतपूर्व समर्थन देकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जनहित के फैसलों का स्वागत किया है और उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में हुए चार फेजों में भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिला है, बाकी बचे तीन फेजों में भी इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद देकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनायेगी। ■

कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड 271.98 मिलियन टन होने का अनुमान

चावल 108.86 मिलियन टन और गेहूं 96.64 मिलियन टन

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2016-17 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों को 15 फरवरी, 2017 को जारी किया गया है। विभिन्न फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त प्रतिपुष्टियों तथा इसकी वैध्यता अन्य स्रोतों से उपलब्ध सूचना पर आधारित है। वर्ष 2003-04 से आगे के वर्षों के तुलनात्मक अनुमानों की तुलना में 2016-17 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा संलग्न है।

2. दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2016-17 के दौरान मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार हैः

खाद्यान्न – 98 मिलियन टन (रिकार्ड), चावल – 108.86 मिलियन टन (रिकार्ड), गेहूं – 96.64 मिलियन टन (रिकार्ड), मोटे अनाज – 44.34 मिलियन टन (रिकार्ड), मक्का – 26.15 मिलियन टन (रिकार्ड), दलहन – 22.14 मिलियन टन (रिकार्ड), चना – 9.12 मिलियन टन, तूर – 4.23 मिलियन टन (रिकार्ड) , उड़द – 2.89 मिलियन टन (रिकार्ड), तिलहन – 60 मिलियन टन (रिकार्ड), सोयाबीन – 14.13 मिलियन टन, मूंगफली – 8.47 मिलियन टन, अरंडी बीज – 1.74 मिलियन टन, कपास – 51 मिलियन गांठे (प्रति 170 कि०ग्रा० की), गन्ना – 98 मिलियन टन

मानसून 2016 के दौरान अच्छी वर्षा एवं सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप, मौजूदा वर्ष में देश में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। 2016-17 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 271.98 मिलियन टन तक अनुमानित है जो 2013-14 के दौरान प्राप्त विगत 265.04 मिलियन टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.94 मिलियन टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन भी विगत पांच वर्षों (2011-12 से 2015-16) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 14.97 मिलियन टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन विगत वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 20.41 मिलियन टन अधिक है।

चावल का कुल उत्पादन 108.86 मिलियन टन जो एक नया रिकार्ड भी है, अनुमानित है। इस वर्ष चावल का उत्पादन 2013-14 के दौरान प्राप्त विगत 106.65 मिलियन टन रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 2.21 मिलियन टन अधिक है। यह पांच वर्षों के 105.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में भी 3.44 मिलियन टन अधिक है। चावल के उत्पादन में 2015-16 के दौरान 104.41 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 4.45 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

गेहूं का उत्पादन जो 96.64 मिलियन टन जो एक रिकार्ड भी है, अनुमानित है। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 2013-14 के दौरान प्राप्त 95.85 मिलियन टन विगत रिकार्ड उत्पादन की तुलना में अधिक है। 2016-17 के दौरान गेहूं का उत्पादन भी औसत गेहूं उत्पादन की तुलना में 4.03 मिलियन टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन 2015-16 के दौरान प्राप्त 92.29 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की तुलना में 4.36 मिलियन टन अधिक है। मोटे अनाजों का उत्पादन जो 44.34 मिलियन टन के एक नए रिकार्ड स्तर पर अनुमानित है, औसत उत्पादन की तुलना में 3.00 मिलियन टन अधिक है। यह 2010-11 के दौरान प्राप्त 43.40 मिलियन टन विगत रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 0.94 मिलियन टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन भी 2015-16 के दौरान प्राप्त 38.52 मिलियन टन उनके उत्पादन की तुलना में 5.82 मिलियन टन अधिक है।

सभी मुख्य दलहनों के क्षेत्रीय कवरेज एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप, 2016-17 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 22.14 मिलियन टन तक अनुमानित है जो 2013-14 के दौरान प्राप्त 19.25 मिलियन टन विगत रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 2.89 मिलियन टन अधिक है। 2016-17 के दौरान दलहनों का उत्पादन भी पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 4.50 मिलियन टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन विगत वर्ष के 16.35 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 5.79 मिलियन टन अधिक है।

विगत वर्ष की तुलना में 8.35 मिलियन टन की वृद्धि के साथ, देश में कुल तिलहन उत्पादन 33.60 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर अनुमानित है। यह 2013-14 के दौरान प्राप्त 32.75 मिलियन टन विगत रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 0.85 मिलियन टन अधिक है। 2016-17 के दौरान तिलहनों का उत्पादन भी पांच वर्षों के औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 4.34 मिलियन टन अधिक है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन 2015-16 के दौरान 25.25 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है।

गन्ने का उत्पादन 309.98 मिलियन टन तक अनुमानित है जो विगत वर्ष के 348.45 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 38.46 मिलियन टन कम है। 2016-17 के दौरान कम क्षेत्रीय कवरेज के बावजूद, कपास की उच्चतर उत्पादकता के परिणामस्वरूप, 2015-16 के दौरान 30.01 मिलियन गांठों की तुलना में 32.51 मिलियन गांठों (प्रति 170 कि०ग्रा०) का अधिक उत्पादन हुआ। 10.06 मिलियन गांठों (प्रति 180 कि.ग्रा. की) तक अनुमानित पटसन एवं मेस्टा का उत्पादन विगत वर्ष के दौरान 10.52 मिलियन गांठों के उत्पादन की तुलना में मामूली रूप से कम है। ■

हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट के मूल्यों में 380 प्रतिशत की कमी

देश के सभी हृदय रोगियों के लिये राहत: अनंत कुमार

सबको सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का अभियान

सबके लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार ने हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट की मूल्य सीमा तय करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह सूचना 14 फरवरी को रसायन एवं उर्वरक तथा संसदीय कार्यमंत्री श्री अंनत कुमार ने दी। मंत्री महोदय ने कहा कि इस कदम से स्टंट की कीमतों में लगभग 380 प्रतिशत की कमी आ जायेगी।

श्री अनंत कुमार ने बताया कि बाजार में बेयर मेटल स्टंट (बीएमएस) का 10 प्रतिशत हिस्सा है। उसकी कीमत 7260 रुपये सीमित कर दी गई है। इसी तरह ड्रग एल्यूटिंग स्टंट (डीईएस) का बाजार में 90 प्रतिशत हिस्सा है, जिसकी कीमत 29,600 रुपये सीमित कर दी गई है। कीमतों में वैट और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि स्टंट पर तमाम राज्यों में 5 प्रतिशत वैट लगाया जाता है, जिसके हिसाब से बीएमएस और डीईएस का खुदरा मूल्य क्रमशः 7623 रुपये और 31,080 रुपये होगा। उन्होंने बताया कि 60 दिन के अंदर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने यह कीमतें तय की हैं।

श्री अनंत कुमार ने कहा कि पहले स्टंटों की बिक्री से मनमाना नफा कमाया जाता था, जिस पर इस निर्णय से बहुत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि बहरहाल नई कीमतों से उद्योगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले बीएमएस का खुदरा मूल्य 45,000 रुपये और डीईएस का 1,21,000 रुपये था। अब बीएमएस की कीमत घटकर 7623 और डीईएस की 31,080 हो गई है। इस तरह मरीजों को औसतन 80-90 हजार रुपये का लाभ होगा।

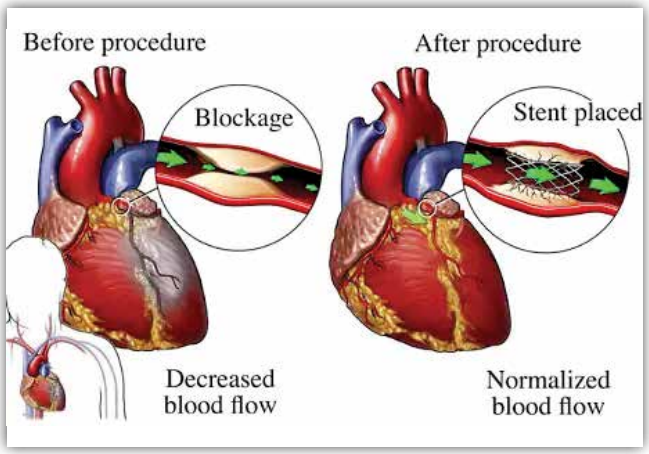

श्री अनंत कुमार ने आश्वासन दिया कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लिखेंगे कि कीमतों को बढ़ने से रोका जाये तथा डॉक्टरों की फीस और अस्पताल में मरीज के रहने की अवधि के संबंध में निगरानी रखी जाये ताकि कीमतों की कमी का लाभ मरीजों को मिल सके। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जो स्टंट पहले से जमा हैं, उनकी कीमतों में भी संशोधन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अगर तयशुदा कीमतों की अवलेहना होती है तो एनपीपीए को यह अधिकार दिया गया है कि वह अतिरिक्त कीमत को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करे।

> बाजार में बेयर मेटल स्टंट (बीएमएस) का 10 प्रतिशत हिस्सा है। उसकी कीमत 7260 रुपये सीमित कर दी गई है। इसी तरह ड्रग एल्यूटिंग स्टंट (डीईएस) का बाजार में 90 प्रतिशत हिस्सा है, जिसकी कीमत 29,600 रुपये सीमित कर दी गई है। कीमतों में वैट और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि स्टंट पर तमाम राज्यों में 5 प्रतिशत वैट लगाया जाता है, जिसके हिसाब से बीएमएस और डीईएस का खुदरा मूल्य क्रमशः 7623 रुपये और 31,080 रुपये होगा।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 'फार्मा जन समाधान' और 'फार्मा सही दाम' नामक दो मोबाइल एप्प शुरू किये हैं। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति मंत्रालय के पास शिकायत भेज सकता है। उन्होंने कहा कि नई कीमतों से 'मेक इन इंडिया' को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा।

श्री अनंत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट को 19 जुलाई, 2016 को आवश्यक औषधि सूची 2015 में शामिल किया था। इसी तरह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने 21 दिसंबर, 2016 को हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 की अनुसूची 1 में शामिल किया था।

इस अवसर पर औषध विभाग के सचिव श्री जय प्रिय प्रकाश, एनपीपीए के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह और एनपीपीए की सदस्य सचिव श्रीमती शर्मिला मैरी जोसेफ और अन्य विशिष्टजन भी उपस्थित थे। ■

'ताम्र' पोर्टल और मोबाइल एप लांच

खनन परिचालन हुआ और पारदर्शी

केन्द्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने 15 फरवरी को पारदर्शिता, नीलामी निगरानी एवं संसाधन संवर्धन (ताम्र-टीएएमआरए) पोर्टल और मोबाइल एप को लांच किया। इस पोर्टल और एप को खान मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसे 12 खनिज समृद्ध राज्यों में एक साथ लांच किया गया। श्री गोयल ने यह महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि सरकार 100 चिह्नित अपतटीय खनिज ब्लॉकों के लिए खोज एवं खनन लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खनन नियमों में जल्द ही संशोधन करने पर विचार कर रही है।

> खनन क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के एक हिस्से के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 'ताम्र' भारत में खनन गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है।

'ताम्र' की खूबियों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए श्री गोयल ने कहा कि खनन क्षेत्र में कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के एक हिस्से के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 'ताम्र' भारत में खनन गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है और इससे समस्त हितधारकों को खनन ब्लॉकों से जुड़ी वैधानिक मंजूरियों की ताजा स्थिति को जानने में मदद मिलेगी। यह वैधानिक एवं अन्य मंजूरियों की समय सीमा को कम करने की दिशा में सभी हितधारकों के लिए एक परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि इससे उत्पादन शुरू होने से पहले लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। 'ताम्र' की खासियतों का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि किसी मंजूरी की प्राप्ति में देरी होने की स्थिति में 'ताम्र' संबंधित प्राधिकरण को सक्रिय करने वाला संदेश (ट्रिगर) भेजेगा, ताकि इसके लिए जवाबदेह माने जाने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा तत्काल सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।

इससे पहले खान सचिव श्री बलविंदर कुमार ने अपने संबोधन में यह जानकारी दी कि 'ताम्र' नीलाम की जाने वाली खदानों की ब्लॉक-वार, राज्य-वार एवं खनिज-वार सूचनाओं को कवर करता है, विभिन्न वैधानिक मंजूरियों पर नजर रखता है और ई-नीलामी के जरिये हासिल किये गये अतिरिक्त संसाधनों पर प्रकाश डालता है। ■

राष्ट्र जीवन की समस्याएं

भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता एवं मौलिक विचारक थे। देशभर में उनकी जन्मशताब्दी वर्ष (2016-17) के अवसर पर संगोष्ठियों का आयोजन एवं पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। कमल संदेश में भी हम उनके द्वारा लिखे गए विचारशील लेखों को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। निम्न लेख 1962 में प्रकाशित पुस्तक 'राष्ट्र चिंतन' से साभार (प्रथम भाग गतांक में प्रकाशित हो चुका है) प्रस्तुत है।

प. दीनदयाल उपाध्याय

संस्कृतियों का संघर्ष :

आज भी भारत में प्रमुख समस्या सांस्कृतिक ही है। वह भी आज दो प्रकार से उपस्थित है, प्रथम तो संस्कृति को ही भारतीय जीवन का प्रथम तत्त्व मानना तथा दूसरे यदि इसे मान लें तो उस संस्कृति का रूप कौन सा हो? विचार के लिए यद्यपि यह समस्या दो प्रकार की मालूम होती है, किंतु वास्तव में है एक ही। क्योंकि एक बार संस्कृति का जीवन को प्रमुख एवं आवश्यक तत्त्व मान लेने पर उसके स्वरूप के संबंध में झगड़ा नहीं रहता, न उसके संबंध में किसी प्रकार का मतभेद ही उत्पन्न होता है। यह मतभेद तो तब उत्पन्न होता है जब अन्य तत्त्वों को प्रधानता देकर संस्कृति को उसके अनुरूप उन ढाँचों में ढ़कने का प्रयत्न किया जाता है।

इस दृष्टि से देखें तो आज भारत में एक-संस्कृतिवाद, द्वि-संस्कृतिवाद तथा बहुसंस्कृतिवाद के नाम से तीन वर्ग दिखाई देते हैं। एक-संस्कृतिवाद के पुरस्कर्ता भारत में केवल एक ही भारतीय संस्कृति का अस्तित्व मानते हैं तथा अन्य संस्कृतियों का या तो अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं हैं या उसके लिए आवश्यक समझते हैं कि वह भारतीय संस्कृति में विलीन हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कांग्रेस में श्री पुरुषोत्तमदास टंडन प्रभृति व्यक्ति इसी एक-संस्कृतिवाद के पोषक हैं।

द्वि-संस्कृतिवादी :

द्वि-संस्कृतिवादी दो प्रकार के हैं। एक तो स्पष्ट तथा दूसरे प्रच्छन्न। एक वर्ग भारत में स्पष्टतया दो संस्कृतियों का अस्तित्व मानता है तथा उनको बनाए रखने की मांग करता है। मुस्लिम लिगी इसी मत के हैं। ये हिंदू और मुसलिम दो संस्कृतियों को मानते हैं तथा उनका आग्रह है कि मुसलमान अपनी संस्कृति की रक्षा अवश्य करेगा। दो संस्कृतियों के आधार पर ही उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत सामने रखा, जिसके परिणाम को हम पिछले दो वर्षों में भली-भाँति अनुभव कर चुके हैं। प्रच्छन्न द्वि-संस्कृतिवादी वे लोग हैं जो स्पष्टतया तो दो संस्कृतियों का अस्तित्व नहीं मानते, भूल से एक संस्कृति एवं एक राष्ट्र का ही राग अलापते हैं, किंतु व्यवहार में दो संस्कृतियों को मानकर उनका समन्वय करने का असफल प्रयत्न करते हैं। वे ये तो मान लेते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो संस्कृतियाँ हैं, किंतु उनको मिलाकर एक नवीन हिंदुस्तानी संस्कृति बनाना चाहते हैं। अतः हिंदी-उर्दू का प्रश्न वे हिंदुस्तानी बनाकर हल करना चाहते हैं तथा अकबर को राष्ट्र पुरुष मानकर अपने राष्ट्र के महापुरुषों के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। 'नमस्ते' और 'सलामवालेकुम' का काम ये 'आदाब अर्ज' से चला लेना चाहते हैं। यह वर्ग कांग्रेस में बहुमत में है। दो संस्कृतियों के मिलाने के अब तक असफल प्रयत्न हुए हैं, किंतु परिणाम विघातक ही रहा है। मुख्य कारण यह है कि जिसको मुसलिम संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है वह किसी मजहब की संस्कृति न होकर अनेक अभारतीय संस्कृतियों का समुच्चय मात्र है। फलतः उसमें विदेशीपन है, जिसका मेल भारतीयत्व से बैठना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसलिए यदि भारत में एक संस्कृति एवं एक राष्ट्र को मानना है तो वह भारतीय संस्कृति एवं भारतीय हिंदू राष्ट्र जिसके अंतर्गत मुसलमान भी आ जाते हैं, के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता।

भारत में एक-संस्कृतिवाद, द्वि-संस्कृतिवाद तथा बहुसंस्कृतिवाद के नाम से तीन वर्ग दिखाई देते हैं। एक-संस्कृतिवाद के पुरस्कर्ता भारत में केवल एक ही भारतीय संस्कृति का अस्तित्व मानते हैं तथा अन्य संस्कृतियों का या तो अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं हैं या उसके लिए आवश्यक समझते हैं कि वह भारतीय संस्कृति में विलीन हो जाए।

बहु-संस्कृतिवादी :

बहु-संस्कृतिवादी वे लोग हैं जो प्रांत की निजी संस्कृति मानते हैं तथा उस प्रांत को उस आधार पर आत्मनिर्णय का अधिकार देकर बहुत कुछ अंशों में स्वतंत्र ही मान लेते हैं। साम्यवादी एवं भाषानुसार प्रांतवादी लोग इस वर्ग के हैं। वे भारत में सभी प्रांतों में भारतीय संस्कृति की अखंड धारा का दर्शन नहीं कर पाते।

संस्कृति से भिन्न जीवन का आधार :

उपरोक्त तीनों प्रकार के वर्गों का प्रमुख कारण यह है कि उनके सम्मुख संस्कृति-प्रधान जीवन न होकर मजहब, राजनीति अथवा अर्थनीति प्रधान जीवन की है। मुसलिम लीग ने अपने अमूर्त तत्त्व का आधार मुसलिम मजहब समझकर ही भिन्न मुसलिम संस्कृति एवं राष्ट्र का नारा लगाया तथा उसके आधार पर ही अपनी सब नीति निर्धारित की। कांग्रेस का जीवन एवं लक्ष्य राजनीति प्रधान होने के कारण उसने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए तथा शासन चलाने के लिए सब वर्गों को मिलाकर खड़ा करने का विचार किया, जिसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से वर्गों को मिलाकर खड़ा करने का विचार किया, जिसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से यह भी द्वि-संस्कृतिवाद का शिकार बन गईं। बहु-संस्कृतिवादी जीवन को अर्थ प्रधान मानते हैं, अतः वे आर्थिक एकता की चिंता करते हुए सांस्कृतिक एकता की ओर से उदासीन रह सकते हैं।

> केवल एक-संस्कृतिवादी लोग ही ऐसे हैं जिनके समक्ष और कोई ध्येय नहीं है तथा जैसाकि हमने देखा, संस्कृति ही भारत की आत्मा होने के कारण वे भारतीयता की रक्षा एवं विकास कर सकते हैं।

एक राष्ट्र और एक संस्कृति :

केवल एक-संस्कृतिवादी लोग ही ऐसे हैं जिनके समक्ष और कोई ध्येय नहीं है तथा जैसाकि हमने देखा, संस्कृति ही भारत की आत्मा होने के कारण वे भारतीयता की रक्षा एवं विकास कर सकते हैं। शेष सब तो पश्चिम का अनुकरण करके या तो पूँजीवाद अथवा रूस की तरह आर्थिक प्रजातंत्र तथा राजनीतिक पूँजीवादी का निर्माण करना चाहते हैं। अतः उनमें सब प्रकार की सद्भावना होते हुए भी इस बात की संभावना कम नहीं है कि उनके द्वारा भी भारतीय आत्मा का तथा भारतीयत्व का विनाश हो जाए। अतः आज की प्रमुख आवश्यकता तो यह है कि एक-संस्कृतिवादियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाए। तभी हम गौरव और वैभव से खड़े हो सकेंगे तथा भारत-विभाजन जैसी भावी दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। ■ *समाप्त*

भारत और क्रोएशिया के बीच आर्थिक सहयोग के लिए करार

भारत और क्रोएशिया के बीच आर्थिक सहयोग के समझौते लिए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और क्रोएशिया के उप-प्रधानमंत्री एवं अर्थव्यवस्था मंत्री मिस मार्टिना डेलिक के बीच 14 फरवरी 2017 को क्रोएशिया के जगरेब में करार पर हस्ताक्षर किए गए।

द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को विकसित करने एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और क्रोएशिया ने सितंबर 1994 में ही व्यापार और आर्थिक सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और क्रोएशिया के बीच वर्तमान समझौते इसी निरंतरता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है जो नवंबर 2009 में समाप्त हो गया था।

भारत और क्रोएशिया के बीच वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः 148.86 मिलियन डॉलर, 205.04 मिलियन डॉलर तथा 148.44 मिलियन डॉलर रहा था। पिछले तीन वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार वैश्विक मंदी के बावजूद स्थिर बनी हुई है। ■

अप्रतिम क्रांतिकारी वीर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर (जन्म-28 मई, 1883, मृत्यु-26 फरवरी, 1966) न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि वे एक भाषाविद्, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, द्रष्टा, महान कवि, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता थे। उनके इन्हीं गुणों ने उनको महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। वीर सावरकर प्रथम क्रान्तिकारी थे, जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित होने पर माफी मांगी। साथ ही वे एक प्रख्यात समाज सुधारक भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्त्व रखते हैं व एक दूसरे के पूरक हैं। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतया वीर सावरकर के नाम से विख्यात थे।

वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। विनायक दामोदर सावरकर, 20वीं शताब्दी के बड़े हिन्दूवादी थे। उन्हें हिन्दू शब्द से बेहद लगाव था। वह कहते थे कि उन्हें स्वातन्त्र्य वीर की जगह हिन्दू संगठक कहा जाए। उन्होंने जीवन भर हिन्दू हिन्दी हिन्दुस्तान के लिए कार्य किया। वह अखिल भारत हिन्दू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 1937 में वे 'हिन्दू महासभा' के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिन्दू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया था। 1943 के बाद दादर, मुंबई में रहे। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया।

1940 ई. में वीर सावरकर ने पूना में 'अभिनव भारत' नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल-प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसायटी बनाई थी, जो 'मित्र मेला' के नाम से जानी गई। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन कालेपानी की दुहरी सजा मिली। सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल (सेल्यूलर जेल) में रहे। 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश-प्रेम का जज्बा बरकरार रहा और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बरी करना पड़ा। मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूं। देश सेवा में ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की।

उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें 'भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध', 'मेरा आजीवन कारावास' और 'अण्डमान की प्रतिध्वनियां' (सभी अंग्रेजी में) अधिक प्रसिद्ध हैं। जेल में 'हिंदुत्व' पर शोध ग्रंथ लिखा। 1909 में लिखी पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस-1857' में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई घोषित की थी।

वीर सावरकर कलम-कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखीं। कहा जाता है उन्होंने अपनी रची दस हजार से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्षों स्मृति में सुरक्षित रखा, जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गई। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी, 1966 में मुम्बई में हुई थी। वीर सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। सच तो यह है कि महान् देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अपने राष्ट्रवादी विचारों से जहां सावरकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे वहीं दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के बाद भी उनका जीवन संघर्षों से घिरा रहा। ■

वीर सावरकर के कुछ प्रमुख कार्य

- सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के केन्द्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया ।
- सावरकर ने सन् 1905 के बंग-भंग के बाद सन् 1906 में 'स्वदेशी' का नारा दे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई।
- सावरकर ने सन् 1857 की लड़ाई को भारत का 'स्वाधीनता संग्राम' बताते हुए लगभग एक हज़ार पृष्ठों का इतिहास लिखा।
- सावरकर ने कलम-काग़ज़ के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कवितायें लिखीं। कहा जाता है उन्होंने अपनी रची दस हज़ार से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्षोंस्मृति में सुरक्षित रखा, जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुच गई।
- वे प्रथम क्रान्तिकारी थे, जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित होने पर माफी मांगी।

विकास-प्रक्रिया में सहकारिता की महती भूमिका: पी. मुरलीधर राव

भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। भाजपा देशभर में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 'महा प्रशिक्षण अभियान' चला रही है। इसका उद्देश्य है कार्यकर्ताओं को निरंतर परिमार्जित करने हेतु पार्टी की विचारधारा व कार्यपद्धति से अवगत कराना। इसी क्रम में भाजपा ने सहकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की भी योजना बनाई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पार्टी प्रशिक्षण समिति के सदस्य **श्री पी.मुरलीधर राव** से कमल संदेश के सहायक संपादक **संजीव कुमार सिन्हा** ने बातचीत की। अपनी बेजोड़ सांगठनिक क्षमता एवं वैचारिक प्रखरता के लिए जाने जानेवाले श्री राव ने कहा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में और निर्धनता उन्मूलन के अभियान के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है ताकि सहकारिता से रोजगार संरक्षण और जीवनयापन की सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रस्तुत है मुख्य अंश:

कृपया पहले आप सहकारिता आंदोलन के बारे में बताइए?

सहकारिता को इसके सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से परस्पर स्वीकृत भाव या कार्य के प्रोत्साहन के लिए एक संगठन के रूप में देखा जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जहां वर्तमान दोनों पार्टियों के लिए पर्याप्त संसाधन हों या उनकी अंत:प्रक्रिया द्वारा निर्माण किया जा सकता हो। इसमें जीवन के सामाजिक पहलुओं का निर्माण होता है और स्वतंत्रता एवं समानता के आधार पर नए लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का उद्देश्य निहित रहता है, जहां लोग एक परिवार की तरह सद्भावना, आपसी चिंता और भागीदारी के साथ रहते हैं, जहां भावना की एकता एवं समान आर्थिक बंधन की भागीदारी रहती है। सहकारिता को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों से उन्मूलन की भूमिका निभानी होती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से दृढ़ और स्थायी रास्ता बनाना होता है।

भाजपा किस प्रकार से सहकारिता आंदोलन को सशक्त करती है?

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में और निर्धनता उन्मूलन के अभियान के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है ताकि सहकारिता से रोजगार संरक्षण और जीवनयापन की सुविधा उपलब्ध हो सके। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ ने अपनी ओर से पहल कर इस अभियान को सशक्त बनाया है जिससे विभिन्न समूहों के लिए ऋण सहायता, कानूनी सहायता सहित अनेक क्षेत्रों को एक नई दिशा मिल सके।

क्या भाजपा के पास सहकारी नेताओं को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? यदि ऐसा है तो क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है?

भाजपा प्रशिक्षण अभियान में राजनीतिक नेतृत्व और सामाजिक सेवा संबंधी विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें सहकारिता क्षेत्र भी शामिल हैं। विशेष ध्यान इस बात पर भी दिया जाता है कि कार्यकर्ता और नेतागण प्रशिक्षित हों, जो सहकारिता क्षेत्र में कार्य करते हों। भाजपा एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसमें सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, साथ ही समाज पर इसके प्रभाव को देखा जाए, सर्वोत्तम प्रक्रियाएं अपनाई जाएं और इस क्षेत्र से संबंधित कौशल आदि पर भी ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम

को तैयार करने में सहकारी सोसाइटियों के चेयरपर्सनों को शामिल किया जाएगा और भाजपा के नेतृत्व में काम कर रही विभिन्न सहकारी संस्थाओं और संगठनों के नेताओं तथा भाजपा शासित राज्यों के विभागों के तहत काम कर रही विभिन्न सहकारी संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर अन्य राज्यों में सहकारिता उद्यम ज्यादा मजबूत नहीं है, अत: अन्य राज्यों के बारे में क्या योजना है?

हमारे देश में सहकारिता अभियान ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विकास किया है। लगभग 6.10 लाख सहकारी सोसाइटियों के नेटवर्क और 249.20 मिलियन सदस्यों के नेटवर्क को देखते हुए भारत का सहकारिता अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। सहकारिता के माध्यम से कृषि क्रेडिट की एडवांस राशि ने बड़ी मात्र में बढ़ोतरी की है जिससे यह 1960–61 में मामूली सी 214.35 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में 86185 करोड़ रुपए तक जा पहुंची जिससे कुछ संस्थागत कृषि ऋण बढ़कर लगभग 17 प्रतिशत शेयर में बदल गया। उर्वरक वितरण में सहकारिता का शेयर 36 प्रतिशत है और चीनी उत्पादन में लगभग 39.7 प्रतिशत है। सहकारिता द्वारा गेहूं प्राप्ति भी लगभग 24.8 प्रतिशत है। खुदरा उचित मूल्य की दुकानों पर सहकारिता क्षेत्र में वितरण की सांझेदारी 54 प्रतिशत और 20.3 प्रतिशत है।

> भाजपा एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसमें सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, साथ ही समाज पर इसके प्रभाव को देखा जाए, सर्वोत्तम प्रक्रियाएं अपनाई जाएं और इस क्षेत्र से संबंधित कौशल आदि पर भी ध्यान दिया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करने में सहकारी सोसाइटियों के चेयरपर्सनों को शामिल किया जाएगा और भाजपा के नेतृत्व में काम कर रही विभिन्न सहकारी संस्थाओं और संगठनों के नेताओं तथा भाजपा शासित राज्यों के विभागों के तहत काम कर रही विभिन्न सहकारी संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सहकारिता क्षेत्र प्रत्यक्ष और स्वरोजगार क्षेत्र में देश में लगभग 17.80 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष तथा स्वरोजगार देता है और मत्स्यपालन, श्रम, हैण्डलूम सेक्टरों और महिला सहकारिताओं के जरिए समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 'श्वेत क्रांति' के माध्यम से डेयरी कोऑपरेटिव दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। आवास सहकारिताएं कमजोर वर्गों और कम आय समूहों के लिए मकान निर्माण में समुचित दरों पर अपना योगदान दे रहा है। उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से कॉऑपरेटिव समाज के कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। इस प्रकार कोऑपरेटिव पर्याप्त रूप से हमारे प्रयासों को फलीभूत कर रहा है, जिसमें विकास भी शामिल है। यह दो प्रमुख राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र और गुजरात में सफल रहा है। क्रेडिट, बैंकिंग ढांचा, जीवनयापन, शिक्षा में असंतुलन होने के कारण अन्य राज्यों ने थोड़ा बहुत कार्य किया है, परन्तु जागरूकता, साक्षरता और सहकारिता अभियान चलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है।

बहुत हद तक सहकारिता उद्यम निष्क्रिय बन गए हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

देश के युवाओं की समर्थता और ऊर्जा को देखते हुए सहकारिता अभियान को उल्लेखनीय तथा राष्ट्र निर्माण मुद्दों पर एक नई पहचान की दिशा दी जानी चाहिए, जिसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दोनों तरह से युवा तथा वंचित वर्गों द्वारा अपनाया जा सकता है। मेक इन इंडिया, स्किल इण्डिया, मुद्रा योजना आदि योजनाएं लघु उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा एवं रोजगार निर्माण में सहायक हो रही हैं।

सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए केन्द्रीय भाजपा सरकार और राज्य सरकारें क्या नए उपाए कर रही हैं?

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी भाजपा सरकार देश के विकास के लिए कई नए उपाए कर रही है, जैसे कि कन्या शिक्षा की उन्नति के लिए सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण, जन–धन योजना कार्यान्वयन, 6 करोड़ लघु विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए वित्तीयकरण, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक 61 प्रतिशत हैं और बैंकिंग सेक्टर में शामिल वित्तीय स्थिति के लिए 14 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। निर्धन लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने डीबीटी को कार्यान्वित किया है जिससे सब्सिडी ठीक लक्षित व्यक्ति तक सीधे पहुंच सके। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हैल्थ कार्ड योजना की शुरूआत की जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ सके, जिसके बारे में कांग्रेस ने विगत 60 वर्षों में सोचा तक नहीं। भाजपा सरकार ने निर्धन तथा वंचित वर्गों की व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रावधान किए और साथ ही गरीबों के लिए स्वास्थ्य और हाईजीन मुद्दे लिए गए, भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विकास हुए, कौशल मीडिया मंत्रालय की स्थापना कर युवाओं के लिए रोजगार सृजन किए गए, हम 'मेक इन इण्डिया', केन्द्र शासित क्षेत्रों के पुलिस बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण, कोयला नीलामी द्वारा 3 लाख करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार निर्माण आदि के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए नए उपायों से मुझे विश्वास है सहकारिता भी अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित हो सकेगी। ■

मुकाबले से बाहर होती कांग्रेस, भाजपा का बढ़ता जनाधार

| अरुण जेटली |

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और एनडीए अपार जनादेश के साथ सत्ता में आया। ये चौंकाने वाला नतीजा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कांग्रेस पार्लियामेंट में सिर्फ 44 सीटों पर सिमट कर रह गई।

बहरहाल, मई 2014 के बाद कई राज्यों में विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव हो चुके हैं। इन सारे चुनावों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र, हरियाणा और असम में इसने खासी सफलता हासिल की। अब तक इन राज्यों में वह क्षेत्रीय पार्टियों की जूनियर सहयोगी की भूमिका निभाती रही थी। अब ओडिशा और महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव नतीजों ने दिखा दिया है भाजपा ज्यादातर राज्यों में अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखती है। इन चुनावों का पहला संदेश यही है कि भाजपा अब एक अखिल भारतीय पार्टी बन चुकी है और इसकी जड़ें पूर्वी ओर दक्षिणी राज्यों में भी तेजी से फैल रही हैं। कर्नाटक में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा मजबूत होकर उभरेगी।

लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है? ओडिशा में इसका कद इतना घट गया है वह मुकाबले से बाहर है। महाराष्ट्र के कई शहरों में यह तीसरे या चौथे स्थान पर खिसक आई है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे कई प्रमुख राज्यों में तो यह मुख्य मुकाबले में ही नहीं है। इन राज्यों में यह छोटे खिलाड़ी के तौर पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन की कोशिश में लगी है। सपा के अंदर भी कई लोग यही सोच रहे हैं कि क्या कांग्रेस में इतना दम है कि उसके लिए यूपी में 103 विधानसभा सीटें छोड़ी जाएं।

क्या कांग्रेस अपने अंदर झांक कर इस हालात पर गौर करेगी? मतदाताओं ने इसे सत्ता से तो बेदखल किया ही है अब वह इसे मुख्य विपक्षी दल की भूमिका नहीं देना चाहते, लेकिन सत्ता से बाहर रह कर भी कांग्रेस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती। संसद में कांग्रेस का जो रवैया है उससे उसकी छवि मुख्यधारा की पार्टी की बजाय छुटभैया पार्टी की बनती जा रही है। यह खुद को शासन करने की क्षमता रखने वाली स्वाभाविक पार्टी के तौर पर पेश करने में नाकाम रही है। इसे सुधार और विकास विरोधी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। 2004 से लेकर 2014 तक के इसके शासन में लगातार बड़े स्कैंडल सामने आते रहे।

नोटबंदी पर कांग्रेस का रवैया उस पर काफी भारी पड़ रहा है। टैक्स की चोरी से देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा गलत तरीके से अमीर होता जा रहा है और सरकारी खजाने को चोट पहुंचा रहा है। इससे सार्वजनिक संसाधन में कमी आ रही है और जनता के एक बड़े वर्ग पर किए जाने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। देश के गरीब लोगों ने नोटबंदी का बढ़-चढ़ कर समर्थन किया है। कांग्रेस गरीब मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को खो चुकी है। ये मतदाता अब भाजपा के पाले में हैं। किसी भी स्थिति में देश पर लगभग पचास साल तक शासन करने वाली पार्टी नकदी के अधिक इस्तेमाल और डिजिटल ट्रांजेक्शन के नए टेक्नलॉजी-टूल्स को स्वीकार करने से कैसे इनकार कर सकती है। कांग्रेस को अपने इस रुख का घाटा उठाना पड़ा है। कांग्रेस एक जिम्मेदार राजनीतिक संगठन की अपनी छवि खो चुकी है। इसकी नीतियों ने इसे आम गरीब आदमी से दूर कर दिया है। जो पार्टी मेरिट पर आधारित नेतृत्व के बजाय वंशवादी राजनीति के वारिसों को आगे बढ़ाती है उसका पतन स्वाभाविक है। ऐसी पार्टी में कद्दावर नेता नहीं हो सकते। पार्टी की ताकत वंशवादी राजनीति के वारिस के करिश्मे के नीचे दब जती है। अगर इस तरह की राजनीति के प्रतिनिधि में पार्टी या देश को आगे बढ़ाने की काबिलियत न हो तो उसे नुकसान पहुंचना स्वाभाविक है। यह डूबते वंशवाद के इर्द-गिर्द सिर्फ एक भीड़ के तौर पर रह जाती है। कांग्रेस के मामले में यही होता दिखता है। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त मंत्री है) (अमर उजाला से साभार)

कृषि क्षेत्र दहाई के आंकड़े में वृद्धि की ओर

कृषि भूमि की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए मृदा जांच कृषि क्रांति की दिशा में एक प्रमुख कदम है, जबकि नीम लेपित यूरिया दूसरा कदम है। इस दिशा में अन्य कदम बांध निर्माण, जलाशयों और अन्य जल संरक्षण विधियों के जरिए जल संरक्षण, भू-जल स्तर बढ़ाना, टपक सिंचाई को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी कम करना, मृदा की उर्वरकता का अध्ययन कर फसलों के तरीकों में बदलाव करना, पानी की उपलब्धता और बाजार की स्थिति है।

| डॉ आर बालाशंकर |

राजग सरकार का कृषि क्षेत्र पर नए सिरे से बल देना, गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने और देश की विकास गाथा में ग्रामीण गरीबों को अभिन्न अंग बनाने की सोची समझी कार्यनीति है। दरअसल इस प्रकार के व्यय से जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया और यह अस्थायी राहत साबित हुआ। लेकिन अनुभव के आधार पर सरकार ने लोगों को एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए योजनाएं शुरू की है।

यह अतीत से आगे बढ़ने का दिलचस्प बिंदु है। सरकार की योजना देश के सबसे पिछड़े जिलों में बदलाव कर इसे भारत में परिवर्तन का मॉडल बनाना है। इसमें कच्छ में गुजरात प्रयोग उपयोगी साबित हो रहा है। इस समय ध्यान देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों पर है, जिनमें से अधिकतर तीन राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। इन तीन राज्यों में ही पूरे देश के 70 सबसे अधिक पिछड़े जिले हैं। दुख की बात यह है कि देश के सबसे विकसित जिलों में से एक भी जिला इन राज्यों में नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि पिछड़े जिलों के मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में पिछड़ेपन और देश के कुछ क्षेत्रों में विकास न होने पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उन्हें प्रथम स्थान पर लाया जा सकता है।

योजना बनाने वाले लंबे समय से क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे पर ढकोसला कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने कई योजनाएं विशेष रूप से

सबसे पिछड़े जिलों के लिए शुरू की। वे शायद इसलिए असफल रही, क्योंकि उनमें अधिक ध्यान गरीबी उन्मूलन और अस्थायी रोजगार सृजन पर दिया गया था। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया था और सड़क सिंचाई तथा संपर्क के अभाव में कृषि क्षेत्रों को भी लाभदायक नहीं बना सके।

प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी ने भूकंप से तबाह हुए और निराश कच्छ के रन को आशावादी भूमि में परिवर्तित कर दिया। श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 से 2014 तक गुजरात में दहाई के आंकड़े की कृषि वृद्धि का युग बनाने का नाबाद रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि उस समय राष्ट्रीय औसत दो प्रतिशत से कम पर था। श्री मोदी ने अगले चार वर्षों में भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने की भी प्रतिज्ञा ली है। गुजरात के कृषि क्षेत्र की इस सफल दास्तां से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कई अन्य राज्यों ने एक ऐसे राज्य की तकनीकों को अपनाया है, जिसे कभी भी कृषि प्रधान राज्य नहीं माना जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण राज्य का विशाल सौराष्ट्र क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष सूखा पड़ने से लोगों और जानवरों का पलायन होता था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि की कार्यनीति बेहतर सिंचाई, खेती के आधुनिक उपकरण, किफायती कृषि ऋण की आसानी से उपलब्धता 24 घंटे बिजली और कृषि उत्पादों का तकनीक अनुकूल विपणन पर तैयार की गई थी। इन प्रत्येक पहलों में बड़ी संख्या में नवीन योजनाएं बनाई और उनका कार्यान्वयन किया गया था। केंद्र की राजग सरकार उनके अनुभव को पूरे देश में दोहराने की कोशिश कर रही है।

कृषि भूमि की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए मृदा जांच कृषि क्रांति की दिशा में एक प्रमुख कदम है, जबकि नीम लेपित यूरिया दूसरा कदम है। इस दिशा में अन्य कदम बांध निर्माण, जलाशयों और अन्य जल संरक्षण विधियों के जरिए जल संरक्षण, भू-जल स्तर बढ़ाना, टपक सिंचाई को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी कम करना, मृदा की उर्वरकता का अध्ययन कर फसलों के तरीकों में बदलाव करना, पानी की उपलब्धता और बाजार की स्थिति है। विद्युतीकरण, पंचायतों में कंप्यूटरीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए सड़क निर्माण के माध्यम से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से जमीनी स्तर पर विकास सुनिश्चित होगा। सड़क निर्माण से प्रत्येक गांव के लिए बाजार और इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

पहली बार देश के इतनी अधिक संख्या में गरीब बैंक खाताधारक बने है। जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ नए खाते खोले गए है। यह वित्तीय समावेशन गतिशील कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र है। वित्तीय वर्ष में सरकार ने सीधे नकद हस्तांतरण के जरिए 50,000 करोड़ रूपये की बचत की है। 50 मिलियन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निःशुल्क रसोई गैस प्रदान करने से लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव आ रहा है। सबसे अधिक वार्षिक आवंटन और कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को दोबारा तैयार किया गया है। इनसे श्रमिकों द्वारा अपनी पारंपरिक कृषि श्रम को छोड़कर शहरों की ओर पलायन भी कम होगा।

कृषि क्षेत्र लाभदायक कैसे बन सकता है? इस दशक के अंत तक कृषकों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है? क्या इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता और किसानों की आत्म हत्या को रोकना सुनिश्चित किया जा सकता है? हां, ये सब संभव हो सकता है अगर प्रधानमंत्री ने जो गुजरात में हासिल किया है उसे राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने में सक्षम होते है तो श्री मोदी ने आम आदमी को अपने आर्थिक गाथा में महत्वपूर्ण स्थान पर रखा है। उन्होंने भारतीय किसानों के प्रति काफी विश्वास व्यक्त किया है और अपनी वृद्धि की परिकल्पना में कृषि को केंद्रीय मंच पर लाये हैं। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आवंटन की नई योजनाओं से इस आकर्षक कहानी का पता लगता है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए अगले वर्ष 1.87 लाख करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। इसके लिए प्रमुख क्षेत्र मनरेगा तथा सरल कृषि ऋण और बेहतर सिंचाई की उपलब्धता है। सिंचाई कोष और डेयरी कोष में काफी वृद्धि की गई है। कृषि ऋण योजना के साथ फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए दस लाख करोड़ दिए गए है जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। अधिक ऋण से कृषि निवेश को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरणा मिलेगी। इससे किसानों को स्थायीत्व और बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

> बेहतर सड़क निर्माण, 2000 किलोमीटर की तटीय संपर्क सड़क और भारत नेट के अंतर्गत 130,000 पंचायतों को उच्च गति के ब्राडबैंड प्राप्त होने से निश्चित रूप से कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में सुधार और बेहतर कीमतें मिलेंगी।

इस मौसम में रबी की आठ प्रतिशत से अधिक फसल लगाई गई है। खबरों में कहा गया है कि बेहतर वर्षा के कारण इस बार खरीफ की फसल रिकॉर्ड 297 मिलियन टन हो सकती है। बेहतर सड़क निर्माण, 2000 किलोमीटर की तटीय संपर्क सड़क और भारत नेट के अंतर्गत 130,000 पंचायतों को उच्च गति के ब्राडबैंड प्राप्त होने से निश्चित रूप से कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में सुधार और बेहतर कीमतें मिलेंगी, जिसके कारण यह एक लाभदायक कैरियर विकल्प हो सकता है। इन नीति संचालित, लक्ष्य आधारित उपायों के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादन में काफी उछाल आयेगा और सभी के लिए भोजन तथा देश से गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त करने का सपना साकार होगा। ■

(लेखक भाजपा केन्द्रीय प्रशिक्षु समिति और प्रकाशन समिति के सदस्य हैं।)

सपा-बसपा सरकार ने बुंदेलखंड के साथ अन्याय किया: नरेंद्र मोदी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-प्रचार के निमित्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अपने भाषणों में वे जनता से आह्वान करते हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जालौन और फूलपुर में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत से लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड को सपा और बसपा ने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा की ऐसी सरकारें बनीं जिसके विधायकों, मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों ने बुंदेलखंड को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू हैं, इन सभी ने बुंदेलखंड के साथ अन्याय किया है। ये बरसों तक बुंदेलखंड को लूटते रहे, इसे विकास से महरूम रखा। उन्होंने कहा कि यदि बुंदेलखंड को विकास पर लाना है तो लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह का भाजपा के विकास का इंजन लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड की समस्याओं के निदान के लिए एक स्वतंत्र 'बुंदेलखंड विकास बोर्ड' का गठन किया जाएगा और सीएम ऑफ़िस से इसका वीकली हिसाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस आज़ादी के इतने दिनों बाद भी बुंदेलखंड को पीने का पानी तक नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि जो बुंदेलखंड को टेकेन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जहां की धरती में पानी-खनिज की ताकत है, वहां का विकास क्यों नहीं हुआ, इसका कारण है- अवैध खनन और हम इसे रोकने के लिए कानून लाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी अपराधीकरण, अत्याचार, भाई-भतीजावाद, मेरे-तेरे में नंबर एक बन गया है। यूपी की स्थिति को बदलने के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता से प्रार्थना करने आया हूं, आप भारी बहुमत देकर हमें सेवा का मौक़ा दीजिये, हर पैरामीटर में हम उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधारने में सफल होंगे। ■

मेरा एक ही मंत्र है - 'सबका साथ, सबका विकास'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आयोजित विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत से लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होती हैं लेकिन आज दलित, शोषित, पीड़ित और गरीब सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हो रहे हैं और सपा की अखिलेश सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि यूपी में न तो नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं न ही उद्योग और कल-कारखाने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए मैं गरीबी के दर्द को समझता हूं, मुझे पता है कि गरीब माताओं को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने में कितना कष्ट होता था। उन्होंने कहा कि हमने ढ़ाई साल में ही लगभग दो करोड़ गरीब माताओं के घरों में गैस सिलिंडर को पहुंचाने का प्रबंध किया है। पांच सालों में मैंने पांच करोड़ गरीब माँओं के घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, काम ऐसे बोलता है। उन्होंने कहा कि हमने कम दाम पर LED बल्ब उपलब्ध कराने का काम किया, जिससे गरीब परिवारों का बिजली बिल बचा। उन्होंने कहा कि पहले देश में यूरिया का दाम कम नहीं होता था,लेकिन चौधरी चरण जी की सरकार के बाद पहली बार हमने यूरिया सहित कई उर्वरकों के दाम कम किये, इतना ही नहीं, यूरिया की नीम कोटिंग की जिससे इसकी कालाबाजारी बंद हुई और किसानों को आसानी से कम दाम पर यूरिया मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने महंगी दवाइयों के दाम को कम करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही मंत्र है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और मैं 'सबका साथ, सबका विकास' के इसी मंत्र के साथ आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि आगामी 11 मार्च को यूपी में भाजपा की भव्य सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। ■

'उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आशा की किरण है भाजपा'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक विशाल जन-सभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत से लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मुझे प्यार दे रहे हैं, उसे मैं विकास के जरिए आपको लौटाऊंगा।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, युवा के लिए होती है, सरकार इन लोगों के लिए होनी चाहिए लेकिन ये समाजवाद की बात करने वाले इंदिरा गांधी के जमाने से 'गरीबी हटाओ' की माला जपने वाले लोगों ने जो चुनाव आते ही गरीब-गरीब करते लगते हैं। न कभी गरीबों के लिए कुछ सोचा और न ही कुछ किया। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार गरीब विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि अन्न सुरक्षा के तहत हमने यूपी सरकार को कहा कि आप गरीबों की सूची बनाइये, केंद्र आपको इतना पैसा देगा कि गरीब परिवारों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन कन्नौज की धरती से बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां से मुलायम, अखिलेश और उनकी पत्नी ने प्रतिनिधित्व किया है, वहां से ये लोग गरीबों की सूची भी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि आप हैरान होंगे, ये यूपी सरकार ऐसी सोई पड़ी है कि अनाथ आश्रम जैसी जगहों पर गरीबों को खाना खिलाने के लिए दिल्ली की सरकार पैसे लेकर बैठी है, लेकिन ये लोग उन्हें खाना नहीं दे पाते और इसका कारण यह है कि इन लोगों को बिचौलिए नहीं मिल पा रहे हैं जो उनका मकसद हल कर सकें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी छोटे किसानों के ऋण माफ़ कर दिए जायेंगे और मैं इस फैसले को लागू कर के रहूंगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 सालों से जिन काले-धन के नोटों के बंडल बनाकर रखे थे, वह सब एक झटके में निकल गया, अब सब हिसाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने देश को लूटा, गरीब को लूटा, उसे अब देश को लौटाना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए एक ही आशा की किरण बची है और वह है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि यूपी में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीबों के लिए होगी, मेहनतकश लोगों के लिए होगी, बहाली में कोई भी भाई-भतीजावाद नहीं होगा, भाजपा मेरिट के आधार पर नौकरी देगी। ■

लखीमपुर खीरी

'14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आयोजित विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2017 का चुनाव बदलाव का चुनाव है, हमें उत्तर प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर ले कर जाना है।

उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आपका काम तो ऐसा बोलता है कि उत्तर प्रदेश की माताएं-बहनें अपने गले में चेन डालने तक से डरती हैं कि कहीं घर के बाहर जाएं तो कोई चेन छीन कर न ले जाये। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आपका काम नहीं बल्कि आपकी पार्टी के दबंग लोगों के काले कारनामे बोलते हैं। आपकी पार्टी द्वारा संरक्षित अपराधी तत्त्वों के पाप बोलते हैं।

उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि जिस प्रदेश में हर रोज दर्जनों बलात्कार की निंदनीय घटनाएं होती हों, हर रोज दर्जनों हत्याएं होती हों और हर हत्या के पीछे कहीं न कहीं राजनीति की बू आती हो। जहां जेल से आपराधिक गैंग चलाये जाते हों, इसे अखिलेश जी का काम कहेंगे या समाजवादी पार्टी के लोगों के कारनामे? उन्होंने कहा कि हर थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है, अपराधियों को सपा-बसपा के राजनीतिक संरक्षण ने यूपी को तबाह करके रख दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि सपा सरकार किसानों के साथ जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो पहली ही बैठक में राज्य के छोटे किसानों की कर्ज माफी का काम किया जाएगा और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा, यह मेरी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर वजन कराने के 14 दिनों के अंदर ही गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मायावती जी के शासन में चीनी मिल की नीलामी का बड़ा तूफ़ान खड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और श्रीमान अखिलेश जी, आपने भ्रष्टाचार की जांच करवाने का वादा जनता से किया था, लेकिन पांच साल हो गए, आप मुझे बताइये कि घोटाले की जांच हुई क्या, क्या यही काम बोलता है आपका? उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, मायावती जी का घोटाला दबाने में आपको क्या मिला, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ■

अखिलेशजी आपके काम नहीं कारनामे बोलते हैं: अमित शाह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-प्रचार के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह अपने भाषणों में जनता से भ्रष्ट सपा सरकार को उखाड़ फेंकने और सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा सरकार लाने का आह्वान कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और कौशांबी में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी - अपना दल गठबंधन की दो-तिहाई बहुमत से लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने की अपील की। जन-सभाओं को संबोधित करने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद में अल्लापुर से घंटाघर तक भव्य रोड शो किया। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे अभूतपूर्व जन-समर्थन और पहले तीन चरणों के संपन्न हुए मतदान से यह साफ़ हो गया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव राज्य से जातिवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को ख़त्म करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने 15 सालों में विकास की दौड़ में पीछे धकेल कर यूपी को बर्बाद कर के रख दिया है। उन्होंने कहा कि सपा-बसपा के शासन में न तो गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंची, न गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, न अस्पताल बने, न शिक्षा में सुधार हुआ, न किसानों के धान की खरीद की गई, न गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान किया गया, न किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिला और न ही युवाओं को रोज़गार मिले। उन्होंने कहा कि विकास के कोई काम नहीं करने के बावजूद अखिलेश यादव कहते हैं कि काम बोलता है, अखिलेश जी, ये आपके काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं की भलाई के लिए काम करने के बजाय उत्तर प्रदेश को हत्या, बलात्कार और लूट जैसे जघन्य अपराधों में नंबर एक बना दिया है। ■

गोरखपुर

'भाजपा की सरकार बनने पर पूर्वांचल विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति और विकास न होने को लेकर सपा-कांग्रेस गठबंधन पर जम कर प्रहार किया।

उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि यूपी में भाजपा की सरकार बनते ही राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों के ऋण पूर्णतया माफ़ कर दिए जायेंगे, साथ ही कृषि के लिए आगे से उन्हें ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने संकल्प पत्र में हमने गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर ही पेमेंट क्लियर कर दिए जाने की व्यवस्था की है, छात्राओं को मुफ्त शिक्षण देने की बात की है, पशुधन की सुरक्षा के लिए यांत्रिक कत्लखानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है और बेहतर शिक्षा के लिए 25 नए मेडिकल कॉलेज और 80 इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि वर्ग तीन और वर्ग चार की बहाली में से इंटरव्यू को ख़त्म किया जाएगा और मेरिट के आधार पर नौकरी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार बनने पर पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि बुनकर सहित जितने भी परंपरागत व्यवसाय हैं, उन्हें न तो यूपी सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है और न ही उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाती है। हमने तय किया है कि इन व्यवसाय में लगे लोगों का कौशल संवर्द्धन किया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पीछे चला गया है, कल-कारखाने बंद पड़े हैं, औद्योगिक पिछड़ापन है, क़ानून-व्यवस्था बदहाल है और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण एक बड़े तबके के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ही उत्तर प्रदेश की इन सारी समस्याओं का निवारण कर सकती है। ■

'छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और अमेठी में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से भ्रष्टाचारी सपा सरकार को जड़ से उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत की विकासोन्मुखी सरकार बनाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर छात्राओं की शिक्षा और उनकी सुरक्षा, दोनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि छात्राओं को ग्रेजुएशन तक की मुफ्त शिक्षा यूपी की भाजपा सरकार उपलब्ध करायेगी और कॉलेजों में उनकी सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि बिना किसी जाति अथवा धर्म के भेदभाव के यूपी की भाजपा सरकार राज्य के हर युवा को 1GB कनेक्टिविटी के साथ मुफ्त लैपटॉप देगी। उन्होंने कहा कि यूपी में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो वर्ग तीन और वर्ग चार की बहाली से इंटरव्यू को ख़त्म कर मेरिट के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था की जायेगी।

राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि सीमा पर तो अब भी गोलीबारी होती है, क्या फर्क पड़ गया मोदी सरकार में। राहुल जी, आपकी आंखों पर इटैलियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको फर्क दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि पहले जब सीमा पर गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और अंत भी पाकिस्तान की सेना ही करती थी, लेकिन अब जब कभी भी सीमा पर गोलीबारी होती है तो इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है लेकिन इसका अंत हिन्दुस्तान की सेना करती है। उन्होंने कहा कि अब दुश्मनों के गोली का जवाब गोले से दिया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, यह फर्क आया है मोदी सरकार में।

भाजपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि आपने सपा, बसपा और कांग्रेस, सबको मौके दिए। एक मौक़ा भारतीय जनता पार्टी को दीजिये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पांच सालों में ही उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बना कर विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। ■

महोबा और बांदा

'दोनों शहजादों में से एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश के महोबा और बांदा में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से भ्रष्टाचारी सपा सरकार को जड़ से उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत की लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं, सुनामी चल रही है। उन्होंने कहा कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या अवध का क्षेत्र हो, चाहे बुंदेलखंड हो या फिर काशी, हर जगह कमल ही कमल दिखाई दे रहा है।

श्री शाह ने कहा कि 15 सालों से सपा, बसपा की सरकारों के क्रम ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में न तो बहन-बेटियां सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित हैं और न ही आम जनता सुरक्षित है, हर तरफ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का आलम है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे, किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा और अखिलेश कहते हैं कि काम बोलता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने गांव, गरीब, किसान, दलित और पिछड़ों की भलाई करने के बजाय उत्तर प्रदेश को हत्या, बलात्कार, लूट और अपहरण जैसी निंदनीय घटनाओं में नंबर एक बना दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था मज़ाक बन कर रह गई है, यूपी में लॉ एंड आर्डर का मतलब हो गया है - लो और आर्डर करो। उन्होंने कहा कि यूपी में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता, हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के संरक्षण में बुंदेलखंड में हजारों करोड़ों रुपये की लूट चल रही है, अगर यूपी में खनन के ठेकेदार चोर नहीं होते तो अकेला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के हर गाँव के अंदर तालाब बनाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार इस लूट को कभी समाप्त नहीं कर सकती, यह उत्तर प्रदेश में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव - इन दोनों शहजादों में से एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को और अब ये दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटने आये हैं। ■

'जो काम कांग्रेस मणिपुर में 15 वर्षों में नहीं कर पाई, वह भाजपा राज्य में सरकार बनने के 15 महीनों में कर के दिखायेगी'

मणिपुर विधानसभा के लिए चार और आठ मार्च को चुनाव होने हैं। इस चुनाव में मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। हालांकि एनपीपी, एनपीएफ और लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले 15 सालों से कांग्रेस है। पिछले छह महीने में कांग्रेस के कई वरिष्ठ सदस्य जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल में आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से मणिपुर के विकास के लिए राज्य की भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ कर भारतीय की विकासोन्मुखी एवं पारदर्शी सरकार बनाने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काम कांग्रेस मणिपुर में 15 वर्षों में नहीं कर पाई, वह भाजपा राज्य में सरकार बनने के 15 महीनों में कर के दिखायेगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर की बर्बादी के लिए कांग्रेस पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, वह मणिपुर को अंधेरे में रखना चाहती है, विकास से महरूम रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो मणिपुर हिन्दुस्तान का स्विट्जरलैंड माना जाता है, उसे कांग्रेस ने 15 सालों में बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि पूर्वी भारत के विकास के बगैर भारत का विकास अधूरा है, हमने सबसे पहले एक्ट ईस्ट नीति पर जोर दिया ताकि पूर्वोत्तर के राज्य भारत के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए मेरे दरवाज़े खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया था लेकिन उसके बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास की कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में पूर्वोत्तर की चिंता करने वाली सरकार है जो पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज पूर्वोत्तर में नियमित रूप से एनईसी की बैठकें होती है, मैंने खुद एनईसी की बैठक में भाग लिया, हमारे कई मंत्री हर महीने पूर्वोत्तर का दौरा करते हैं और पूर्वोत्तर की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि जहां कहीं भी कांग्रेस सत्ता में है, वहां विकास की जगह केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने कहा कि जनजातियों को भड़का कर उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है। नागा पीपुल्स फ्रंट के साथ शांति समझौता लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व हुआ था, आज इसके बारे में मणिपुर के मुख्यमंत्री झूठ फैला रहे हैं, जब समझौता हुआ, तब वे क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर की जनता को अनाज, दवाई, चीनी, नमक, पेट्रोल, डीज़ल और अन्य ज़रूरी सामान उपलब्ध करने की ज़िम्मेदारी मणिपुर की सरकार है, लेकिन यहां की राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को विधान सभा चुनाव के नतीजे आएँगे और 13 मार्च को पूरा हिंदुस्तान होली का उत्सव मनाएगा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और, इसके बाद कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। उन्होंने कहा कि मैं जानकारियों के आधार पर आपसे यह कह रहा हूं कि 3-3 महीने से एनएच को ब्लॉक कर के रखने के बावजूद यदि मणिपुर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि कांग्रेस की इनके साथ मिली-भगत है, एनएच ब्लॉक करके रखने वालों को जेल में क्यों नहीं बंद किया जा रहा, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि यदि नाकेबंदी हटाने के लिए मणिपुर की सरकार मदद मांगेगी तो केंद्र सरकार तुरंत सहायता उपलब्ध करायेगी। उन्होंने मणिपुर की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए राज्य की जनता पर जुल्म किया जा रहा है, उसे कालाबाजारी में समान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसी निर्दयी सरकार को एक मिनट भी मणिपुर की सत्ता में रहने का हक नहीं है।

> चुनाव जीतने के लिए राज्य की जनता पर जुल्म किया जा रहा है, उसे कालाबाजारी में समान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसी निर्दयी सरकार को एक मिनट भी मणिपुर की सत्ता में रहने का हक नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में कांग्रेस ने करप्शन के जो खेल खेले हैं, उन्हें मणिपुर की जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति गरीबों को गरीब बनाए रखने की है, यदि गरीबों के प्रति इनका ये नज़रिया है तो फिर मणिपुर का डेवलपमेंट कैसे होगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर को भारत सरकार सस्ती बिजली देने को तैयार है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को अंधेरे में रखना चाहती है, मणिपुर की कांग्रेस सरकार अपनी पोल खुलने के डर से राज्य के लोगों को बिजली नहीं देती। उन्होंने कहा कि यदि बिजली नहीं आएगी तो कारखाना कौन लगाएगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? ■

पीएसएलवी-सी 37 ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

पीएसएलवी का लगातार 38वां सफल मिशन

इसरो के पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी 37 ने अपनी 39वीं उड़ान में 15 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 103 सहयात्री उपग्रहों सहित 114 किलो कार्टोसेट-2 सीरीज के उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह पीएसएलवी का लगातार 38वां सफल मिशन है। पीएसएलवी-सी 37 ऑनबोर्ड पर ले जाये गये सभी 114 उपग्रहों का कुल भार 1378 किलोग्राम था।

पीएसएलवी ने प्रथम लांच पैड से योजना के अनुसार प्रातः 9:28 बजे (आईएसटी) उड़ान शुरू की। 16 मिनट और 48 सैकंड की उड़ान के बाद उपग्रहों ने ध्रुव की ओर 97.46 डिग्री के कोण पर झुके ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षाओं को प्राप्त कर लिया और बाद के 12 मिनट के समय में सभी 104 उपग्रह सफलतापूर्वक पूर्व निर्धारित क्रम में पीएसएलवी चौथे चरण से सफलतापूर्वक अलग-अलग हो गये। शुरुआत कार्टोसेट-2 सीरीज के उपग्रह से हुई उसके बाद आईएनएस-1 और आईएनएस-2 अलग हुये। पीएसएलवी द्वारा छोड़े गये भारतीय उपग्रहों की संख्या अब 46 हो गई है।

पीएसएलवी-सी 37 द्वारा ले जाये गये 103 सहयात्री उपग्रहों में 2-इसरो नैनो सैटेलाइट-1 (आईएनएस-1) वजन 8.4 किलो और (आईएनएस-2) वजन 9.7 किलोग्राम भारत के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह हैं। बकाया 101 सहयात्री सैटेलाइट उपग्रहों में से अमेरिका के 96 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह हैं।

बिलगन के बाद कार्टोसेट-2 सीरीज के 2 सौर सारणी स्वचालित रूप से तैनात हो गई और इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) ने उपग्रह का नियंत्रण संभाल लिया। आने वाले दिनों में यह उपग्रह अंतिम परिचालन विन्यास में लाया जायेगा। उसके बाद यह अपने पेन्क्रोमेटिक (ब्लैक एंड व्हाइट) और मल्टी स्पेक्ट्रल (रंगीन) कैमरों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर देगा।

पीएसएलवी-सी 37 द्वारा ले जाये गये 103 सहयात्री उपग्रहों में 2-इसरो नैनो सैटेलाइट-1 (आईएनएस-1) वजन 8.4 किलो और (आईएनएस-2) वजन 9.7 किलोग्राम भारत के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह हैं। बकाया 101 सहयात्री सैटेलाइट उपग्रहों में से अमेरिका के 96 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह हैं। इसके अलावा नीदरलैंड, स्विटजरलैंड, इजरायल, कजाखस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के एक-एक उपग्रह शामिल हैं। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत के वर्कहॉर्स प्रक्षेपण यान पीएसएलवी द्वारा छोड़े गये विदेशी ग्राहक उपग्रहों की कुल संख्या बढ़कर 180 तक पहुंच गई है। ■

ई-वीजा सुविधा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं विदेशी पर्यटक

पर्यटन मंत्रालय आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के अनुसार जनवरी, 2016 की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान 16.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो इसी अवधि के दौरान जनवरी, 2015 की तुलना में जनवरी, 2016 की 6.8 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। जनवरी, 2016 में 0.88 लाख की तुलना में 1.52 लाख लोगों द्वारा ई-वीजा पंजीकरण करवाने से जनवरी, 2016 की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान ई-वीजा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में 72 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। स्पष्ट है कि 2017 में ई-वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले पर्यटकों का हिस्सा जनवरी, 2016 के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गया। इससे ई-वीजा सुविधा की सफलता का पता चलता है। पर्यटन मंत्रालय के बदलाव के रुख के बाद जनवरी 2017 से देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन और ई-वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले विदेशी पर्यटकों का मासिक ब्यौरा पेश किया जाएगा।

जनवरी, 2017 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन और ई-वीजा पर विदेशी पर्यटक आगमन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं -

विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) :

- जनवरी, 2017 के दौरान एफटीए का आंकड़ा 9.83 लाख का रहा, जबकि जनवरी, 2016 में यह 8.44 लाख और जनवरी, 2015 में 7.91 लाख था।

- जनवरी, 2016 की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान एफटीए में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जनवरी, 2015 की तुलना में जनवरी, 216 में यह 6.8 प्रतिशत थी।

- शीर्ष 15 स्रोत देशों में जनवरी, 2017 के दौरान भारत में एफटीए में सर्वाधिक हिस्सा अमेरिका (15.01 प्रतिशत) का रहा। इसके बाद हिस्सा क्रमशः बांग्लादेश (14.91 प्रतिशत), ब्रिटेन (11.11 प्रतिशत), कनाडा (4.63 प्रतिशत), रूसी संघ (4.46 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (3.65 प्रतिशत), मलेशिया (3.15 प्रतिशत), जर्मनी (2.92 प्रतिशत), फ्रांस (2.89 प्रतिशत), चीन (2.54 प्रतिशत), श्रीलंका (2.45 प्रतिशत), जापान (2.15 प्रतिशत), अफगानिस्तान (1.84 प्रतिशत), कोरिया गणराज्य (1.61 प्रतिशत), और नेपाल (1.60 प्रतिशत) का रहा।

- शीर्ष 15 हवाई अड्डों पर जनवरी 2017 के दौरान भारत में एफटीए में सर्वाधिक हिस्सा दिल्ली हवाई अड्डा (28.30 प्रतिशत) का रहा। इसके बाद हिस्सा क्रमशः मुंबई हवाई अड्डा (18.23 प्रतिशत), हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट (8.17 प्रतिशत), चेन्नई हवाई अड्डा (7.32 प्रतिशत), गोवा हवाई अड्डा (6.51 प्रतिशत), बेंगलुरू हवाई अड्डा (5.32 प्रतिशत), कोलकाता हवाई अड्डा (4.32 प्रतिशत), कोच्चि हवाई अड्डा (3.73 प्रतिशत), अहमदाबाद हवाई अड्डा (3.37 प्रतिशत), हैदराबाद हवाई अड्डा (2.74 प्रतिशत), गेडे रेल (1.77 प्रतिशत), त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा (1.62 प्रतिशत), त्रिची हवाई अड्डा (1.38 प्रतिशत), गोजदंगा लैंड चैक पोस्ट (1.08), और अमृतसर हवाई अड्डा (1.02 प्रतिशत) का रहा।

ई-वीजा पर विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए)

जनवरी, 2016 में 0.88 लाख पर्यटकों के आगमन की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान ई-वीजा पर कुल 1.52 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ, जो 72.0 प्रतिशत अधिक था।

जनवरी, 2017 के दौरान ई-वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले 15 शीर्ष स्रोत देशों की प्रतिशत भागीदारी निम्नलिखित है-

ब्रिटेन (22.9 प्रतिशत), अमेरिका (13.6 प्रतिशत) और रूस संघ (8.3 प्रतिशत), चीन (6.3 प्रतिशत), फ्रांस (5.6 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (4.4 प्रतिशत), जर्मनी (4.1 प्रतिशत), कनाडा (3.6 प्रतिशत), कोरिया गणराज्य (3.2 प्रतिशत), उक्रेन (2.2 प्रतिशत) नीदरलैंड (1.6 प्रतिशत) दक्षिण अफ्रीका (1.4 प्रतिशत), सिंगापुर (1.3 प्रतिशत), मलेशिया (1.3 प्रतिशत), और स्वीडन (1.1 प्रतिशत)।

जनवरी, 2017 के दौरान ई-वीजा पर शीर्ष 15 हवाई अड्डों की प्रतिशत भागीदारी निम्नलिखित है-

नई दिल्ली हवाई अड्डा (36.5 प्रतिशत), मुंबई हवाई अड्डा (20.5 प्रतिशत), दाबोलिम (गोवा) हवाई अड्डा (16.2 प्रतिशत), चेन्नई हवाई अड्डा (7.0 प्रतिशत), बेंगलुरू हवाई अड्डा (5.1 प्रतिशत), कोच्चि हवाई अड्डा (4.2 प्रतिशत), कोलकाता हवाई अड्डा (2.7 प्रतिशत), त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा (2.0 प्रतिशत), हैदराबाद हवाई अड्डा (2.0 प्रतिशत, अहमदाबाद हवाई अड्डा (1.7 प्रतिशत), अमृतसर हवाई अड्डा (0.8 प्रतिशत), जयपुर हवाई अड्डा (0.5 प्रतिशत), त्रिची हवाई अड्डा (0.4 प्रतिशत), गया हवाई अड्डा (0.2 प्रतिशत) और लखनऊ हवाई अड्डा (0.1 प्रतिशत) ■

कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के अधिग्रहण को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने सहायक बैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 और हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम 1956 को निरस्त करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस विलय से बड़ी बचत होगी जो अनुमानित तौर पर पहले साल में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। साथ ही इनके एक साथ आने से कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और लागत कम होगी। सहायक बैंकों के ग्राहक भारतीय स्टेट बैंक के वैश्विक नेटवर्क का लाभ ले सकेंगे। विलय से उच्च प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और इससे मुद्रा के प्रवाह पर निगरानी व नियंत्रण रखा जा सकेगा। इन छह बैंकों के लिए अलग अलग निगरानी व्यवस्था करने के बजाय एक तंत्र के तहत उपर्युक्त गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 35 के तहत किया

गया है। इससे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सहायक बैंकों के सामने पेश आ रही दिक्कतें कम हो जाएंगी। साथ ही इससे आर्थिक और संचालन में कुशलता के मोर्चे पर सुधार होगा। इससे जोखिम प्रबंधन और एकीकृत ट्रेजरी परिचालन में भी सुधार होगा। सरकारी बैंकों के एकत्रीकरण के जरिये भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का अधिग्रहण बैंक क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। यह सरकार के इंद्रधनुष कार्ययोजना का अनुसरण है और संभावना है कि इससे कार्यकुशलता और लाभ के मामले में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आएगा। ■

भारतीय नौसेना में शामिल हुई 'तारिणी'

समुद्र में चलने वाली सेलबोट आईएनएसवी तारिणी को गोवा में 18 फरवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल श्री सुनील लांबा की उपस्थिति में इसे आईएनएस मनदोवी के बोट पूल में शामिल किया गया। यह नौका भारतीय महिलाओं के सबसे पहले दल को दुनिया की सैर पर लेकर जाएगी, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा अगस्त में शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर एडमिरल श्री सुनील लांबा ने घोषणा की कि उसके सभी महिलाओं क्रू का बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान अगस्त 2017 में शुरू किए जाने की उम्मीद है। महिलाओं के चालक दल के बारे में उन्होंने कहा कि टीम आईएनएसवी महादेई पर 10,000 से अधिक नौटिकल मील की यात्रा कर चुकी है।

आईएनएसीवी तारिणी का निर्माण गोवा की मैसर्स एक्वेरियस शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, दिवर ने किया है। एल्युमिनियम और स्टील की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के लिए नौका का ढांचा लकड़ी और फाइबर ग्लास से बना है। आईएनएसवी तारिणी में 6 सूट हैं। नवनिर्मित आईएनएसवी तारिणी के ट्रायल 30 जनवरी, 2017 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गए थे।

इस नौका की डिजाइन ओडिशा के गंजाम जिले के प्रसिद्ध तारा तारिणी मंदिर से प्रेरित है। तारिणी शब्द का अर्थ होता है नौका और संस्कृत में इसका मतलब होता है तारने वाला। समुद्री नौवहन गतिविधियों और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने विश्व के पहले भारतीय महिला परिनौसंचालन अभियान की परिकल्पना की है। इस परियोजना के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी के नेतृत्व में 6 महिला अधिकारियों के दल का चयन किया गया है। इन अधिकारियों ने आईएनडब्ल्यूटीसी, मुंबई में नौवहन का मौलिक प्रशिक्षण लिया है। ■

कृषि की विकास दर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमानः राधा मोहन सिंह

2016-17 में रबी की बुवाई 6.86 प्रतिशत ज्यादा

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार पांच सालों में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए इस बार के बजट में कृषि के समग्र विकास पर फोकस किया गया है जिसमें किसानों को वहन करने योग्य कर्ज उपलब्ध कराने, बीजों और उर्वरकों की सुनिश्चित आपूर्ति, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उत्पादकता में सुधार लाने, ई-नैम के माध्यम से एक सुनिश्चित बाजार और लाभकारी मूल्य दिलाने पर जोर दिया गया है। यह बात 16 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की 88 वीं वार्षिक आम बैठक में केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कही।

श्री सिंह ने कहा कि कृषि की बेहतरी और किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने बजट में कई पहल की हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में वर्ष 2017-18 के लिए ग्रामीण, कृषि और सम्बद्ध सेक्टर के लिए 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे रूपये 1,87, 223 करोड़ किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र की प्रगति दर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में अच्छे मानसून और सरकार की नीतिगत पहल के कारण इस वर्ष में देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 2016-17 के लिए दूसरे अग्रिम आकलन के अनुसार देश में कुल 271.98 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2013-14 में हासिल 265.04 मिलियन टन खाद्यान्न के पिछले रिकॉर्ड उत्पादन की तुलना में 6.94 मिलियन टन ज्यादा है एवं पिछले वर्ष 2015-16 के मुकाबले वर्तमान वर्ष 2016-17 का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से 20.41 मिलियन टन ज्यादा है।

श्री सिंह ने कहा कि इस बार रबी में पिछले साल 2015-16 की तुलना में गेहूं में 7.71 प्रतिशत, दलहन में 12.96 प्रतिशत और तिलहन में 10.65 प्रतिशत ज्यादा बुवाई हुई है जो कि सभी फसलों को मिलाकर पिछले वर्ष की तुलना में 6.86 प्रतिशत ज्यादा बुवाई है।

श्री सिंह ने कहा कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास करके हरित क्रांति लाने और उत्तरोत्तर कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1951 से लेकर अब तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 5 गुणा, बागवानी उत्पादन में 9.5 गुणा, मत्स्य उत्पादन में 12.5 गुणा, दूध उत्पादन में 7.8 गुणा और अंडा उत्पादन में 39 गुणा की वृद्धि हुई है। इसका राष्ट्रीय खाद्य व पोषणिक सुरक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। हमारे वैज्ञानिकों ने उच्चतर कृषि शिक्षा की उत्कृष्टता बढ़ाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 में देशभर में दलहन के 150 बीज हब स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले परिपक्व होने वाली मूंग की किस्म 'आईपीएम 205-7 (विराट)' को खेती के लिए जारी किया गया। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के प्रयासों में पिछले ढाई वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2012 से मई 2014 तक जहां विभिन्न फसलों की कुल 261 नई किस्में जारी की गई थीं, वहीं लगभग इतनी ही अवधि, जून, 2014 से दिसम्बर, 2016 में कुल 437 नई किस्में जारी की गई हैं।

कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में अक्तूबर 2016 में नई दिल्ली में समन्वय इकाई के साथ कृषि में ब्रिक्स अनुसंधान प्लेटफार्म की स्थापना करने के लिए एक समझौता किया गया। इस इकाई का प्रबंधन डेयर, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2016 में 17 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृषि चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए इसकी प्रगति में राज्यों के माननीय कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस मौके पर प्रतिनिधियों से अपील की कि वे वैज्ञानिक-राज्य-किसान सम्पर्क विकसित करें और कृषि की प्रगति और किसानों की आमदनी व खुशहाली बढ़ाने की दिशा में केन्द्र के साथ मिलकर काम करें।

साथ ही श्री सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 87 साल के अपने अब तक के कार्यकाल में अनेक सफलताएं हासिल की है, जिन्हें कृषि की प्रगति में मील का पत्थर कहा जा सकता है। खेती बाड़ी में उत्पादकता और आय में वृद्धि, संस्थान निर्माण, मानव संसाधन, नई तकनीकों का विकास, कृषि विविधिकरण जैसे क्षेत्रों में आईसीएआर ने सफलता के नये प्रतिमान स्थापित किए हैं। ■

गरीबों के लिए याचिका दाखिल करना आसान हुआ

मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यम आय समूह योजना लागू की है। यह आत्म समर्थन देने वाली योजना है और इसके तहत 60,000 रूपये प्रति महीने और 7,50,000 रूपये वार्षिक आय से कम आय वाले लोगों के लिए कानूनी सहायता दी जाएगी।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860(2) के अन्तर्गत सोसायटी के प्रबंधन का दायित्व गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को दिया गया है। गवर्निंग बॉडी में भारत के प्रधान न्यायाधीश संरक्षक होंगे। अटार्नी जनरल पदेन उपाध्यक्ष होंगे। सोलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया मानद सदस्य होंगे और उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य होंगे।

उच्चतम न्यायालयों के नियमों के अनुसार न्यायालय के समक्ष याचिका केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिये दाखिल की जा सकती है। सेवा शुल्क के रूप में उच्चतम न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसाइटी (एससीएमआईजीएलएएस) को 500 रूपये का भुगतान करना होगा। आवेदक को सचिव द्वारा बताई गई फीस जमा करानी होगी। यह योजना में संलग्न अनुसूची के आधार पर होगी। एमआईजी कानूनी सहायता के अंतर्गत सचिव याचिका दर्ज करेंगे और इसे पैनल में शामिल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड/दलील पेश करने वाले वकील/वरिष्ठ अधिवक्ता को भेजेंगे।

यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इस बात से संतुष्ट हैं कि यह याचिका आगे की सुनवाई के लिए उचित है, तो सोसाइटी आवेदक के कानूनी सहायता अधिकार पर विचार करेगी। जहां तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता का प्रश्न है याचिका के बारे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की राय अंतिम राय मानी जाएगी।

योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के वैसे लोग जो उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमों का खर्च नहीं उठा सकते, वे कम राशि देकर सोसाइटी की सेवा ले सकते है। इस योजना के लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित फार्म भरना होगा और इसमें शामिल सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा। योजना के अनुसार याचिका के संबंध आने वाले विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि बनाई जाएगी। याचिका की स्वीकृति के स्तर तक आवेदक को इस आकस्मिक निधि में से 750 रूपये जमा कराने होंगे। यह सोसाइटी में जमा किये गये शुल्क के अतिरिक्त होगा। यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यह समझते है कि याचिका आगे अपील की सुनवाई योग्य नहीं है, तो समिति द्वारा लिये गये न्यूनतम सेवा शुल्क 750 रूपये को घटाकर पूरी राशि चैक से आवेदक को लौटा दी जाएगी।

समाज के कम आय वर्ग के लोगों के लिए याचिका दाखिल करने के काम को सहज बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह योजना लागू की है।

यदि योजना के अन्तर्गत नियुक्त अधिवक्ता सौंपे गये केस के मामले में लापरवाह माने जाते हैं तो उन्हें आवेदक से प्राप्त फीस के साथ केस को वापस करना होगा। इस लापरवाही की जिम्मेदारी सोसाइटी पर नहीं होगी और मवक्कील से जुड़े अधिवक्ता की पूरी जिम्मेदारी होगी। अधिवक्ता का नाम पैनल से समाप्त कर दिया जाएगा। समाज के कम आय वर्ग के लोगों के लिए याचिका दाखिल करने के काम को सहज बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह योजना लागू की है। ■

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता

और

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

कन्नौज

लखीमपुर

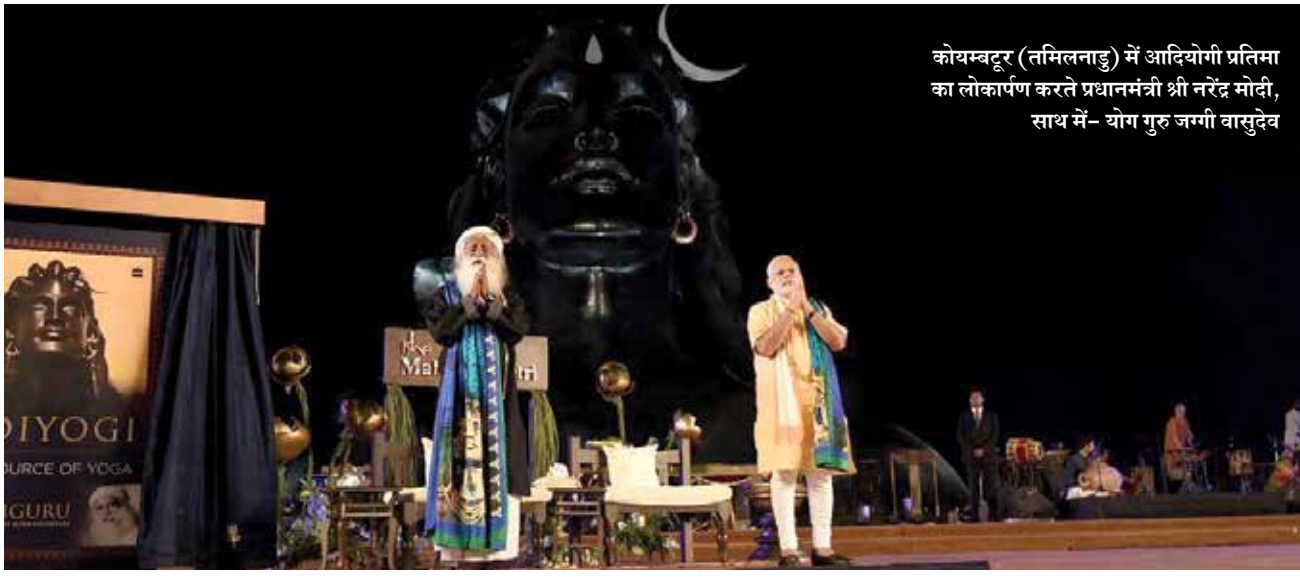

कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में आदियोगी प्रतिमा का लोकार्पण करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, साथ में– योग गुरु जग्गी वासुदेव

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' के हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003